THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K GADHVI): The hon. Member goes on challenging the authority of the Chair It is highly deplorable. When the Chair directs, he does not obey.

SHRI VIRENDRA VERMA (Uttar Pradesh): He has obeyed.

श्री राम अवधेश सिंह : लेकिन मेरी बात भी सुनिये । आप मेरी बात सुनिये (व्यवधान) यही तो मैं कह रहा हूं । आप कुछ क्यो नहीं कहते है । गरीबो की बात यहां नही सुनी जाती है । (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मिस्टर थी०एम० जाधव प्लीज़ ।

श्री राम अवधेश सिंह : आप हमारी बात सुनिये । (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप बैठ जाइये, यह तरीका ठीक नहीं है । यह तरीका नही है पार्लियामेंट मे बोलने का ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : (महाराष्ट्र) . मंत्री महोदय ने जो वित्त विधेयक पेश किया है, मै उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं जो सवाल उठा रहा हूं (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : Whatever you say will not go on record.

श्री राम अवधेश सिंह:*

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : चेयरमैन तो डिसाइड करेंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह :*

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : Let him meet the Chairman. The Chairman will decide it.

श्री राम अवधेश सिंह :*

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप बैठ जाइये, यह ठीक बात नही है । यह कोई तरीका नही है पार्लियामेंट मे काम करने का ।

श्री राम अवधेश सिंह :*

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : सरकार की जिम्मेदारी नही है । आपको चेयरमैन को बताना पड़ेगा । अगर वह नही करते है तो खत्म हो जाएगा । I cannot direct the Government. You go and meet the Chairman. That is all.

श्री राम अवधेश सिंह :*

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) । सुन लिया है । आपकी बात मै नही बोल सकता ।

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE FINANCE (AMENDMENT) ORDINANCE, 1987—Contd.

II. THE FINANCE (AMENDMENT) BILL, 1987—Contd.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : (महाराष्ट्र) उपसभाध्यक्ष महोदय, जो वित्त विधेयक मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हू । जब हम इस वर्ष की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे देश में इतना अधिक सूखा पडा है कि इससे पहले 100 वर्ष में भी इस प्रकार का सूखा नही पड़ा । मुझे बड़ी खुशी है कि पहली बार हमारी सरकार ने इस सूखे की समस्या की तरफ बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया है । उसका मतलब यह नहीं है कि पहले हमने कभी ध्यान ही नही दिया । मगर जहां भी सूखा हुआ है, विशेषकर राजस्थान में और गुजरात में जो सूखे की हालत है वह बहुत गम्भीर है । गये चार-पांच साल मे बहुत सूखा पड़ा हुआ है, हमारे महाराष्ट्र में गये तीन साल मे सूखा पड़ा हुआ है । मगर इस साल 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर हालत अच्छी है । पीने के पानी की समस्या, जानवरों के चारे की समस्या और अन्य बहुत सी समस्याएं इस सूखे ने खड़ी कर दी हैं । मैं आपके

*Not recorded.

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

माध्यम से कहना चाहता हू कि सरकार तो काफी सतर्क है । एक स्टार्ड क्वेश्चन के जवाब मे माननीय वित्त मत्री जी ने कहा था कि सूखे के लिए बाहर की भी मदद ली जा रही है, फोरन एड भी बहुत कुछ आ चुका है, 70-75 करोड़ की एड आई है, इसमे वर्ल्ड बैंक और जापान का बहुत बड़ा हिस्सा है । सरकार भी कुछ, 700-800 करोड रुपये की मदद राज्यों को दे रही है । मुझे माननीय वित्त मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही क्लैरिफिकेशन चाहिए की आप जो 700-800 करोड़ की मदद दे रहे है या दे चुके है और 1500 से 2000 करोड तक पूरा देने की ख्वाहिश हो सकती है तो इसमें फोरन एड इन्क्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है ? मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस करता हू ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने सूखे पर बहस करते हुए कहा था कि सन् 1870 से लेकर 1987 तक इस देश में 24 सूखे हुए है और इनमे से 6 ड्राउट्स 1968 से 1987 तक हुए । इसका मतलब यह है कि सूखे की इन्टेंसिटी 68 मे 87 अर्थात् पिछले 20 साल में ज्यादा बढ़ी है । यह 1987 का जो सूखा है यह महान सूखा है, महान आपातकाल है । मगर इसके बावजूद भी हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति मजबूत है । इस सरकार की जो आर्थिक नीति है उसके फलस्वरूप ही हमारे देश में इस साल चीनी का उत्पादन 36 लाख टन से ज्यादा होने की संभावना है, जबकि गये 4 साल में हमारा उत्पादन गिरा था । मैं कहना चाहता हूं कि हमारा आपोजीशन इस चीज को मानता नहीं है कि हमारी सरकार की नीति सही है... (व्यवधान) जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है उसको आपको मानना चाहिए । बापू जी, जो चीज सामने दिखती है उसको आप कहते हैं कि नहीं है । सामने पुरुष दिखता है तो आप कहते है कि स्त्री है और स्त्री दिखती है तो कहते है कि पुरूष है... (व्यवधान) ऐसी आपोजीशन की नीति क्यों है ।

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : आजकल ऐसा होता है ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : तो मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे यहा चीनी का उत्पादन काफी बढ़ा है, उद्योगधंधों का उत्पादन बढ़ा है । आजादी के बाद से इतना नहीं बढ़ा जितना इस साल बढ़ा है और पिछले 3 साल से कन्टीनुअसली बढता जा रहा है...(व्यवधान) महंगाई भी बढ़ती जा रही है वह अलग बात है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपको जो बोलना होगा बाद में बोलिएगा ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मगर हम देखते है कि आपके जमाने में महंगाई जितनी बढ़ी थी उससे कम बढ़ी है...जब उस वक्त आपका राज था... (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : ये तो कभी गद्दी पर बैठे ही नहीं थे ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : जनता पार्टी की सरकार थी और आप जिस पार्टी के साथ बैठे है उस पार्टी की सरकार थी...(व्यवधान) आपने तो किसानों का गन्ना जला ही दिया था । हमारी सरकार आई तो 85 लाख टन उत्पादन हुआ, मगर कहीं भी ऐसी कम्प्लेंट नही आई कि किसानों का गन्ना शुगर फैक्ट्री ने नही उठाया ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपकी बात नही करते है ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आज भी किसानों को कपास का भाव सौ रुपये बढा है । आपके साथ हम भी सरकार से दरख्वास्त करते है कि और सौ रुपया दिया जाये । हम कहते है सरकार से कि सौ के बजाये दो सौ रुपया दीजिए ...(व्यवधान) महाराष्ट्र मे अच्छा हुआ है । गुजरात जो मेन काटन प्रोड्यूसिंग स्टेट था देश का, उसमें बहुत बड़ा सूखा

होने की वजह से कपास नही हुई, राजस्थान में सूखे की वजह से कपास नही हुई, पजाब मे नही हुई लेकिन महाराष्ट्र मे कपास टिप्पणी कपास अच्छा होने की वजह से क्या हुआ है कि हमारे महाराष्ट्र मे जो काटन मोनोपोली स्कीम है, सारे देश के व्यापारी चाहते है कि इसको फेल किया जाये, इसको उठाया जाये तो किसानों को ज्यादा एक्सप्लायट कर सकेंगे। हमारे बार्डर मे आदिलाबाद मे आध्र प्रदेश मे, महिसा मे और अन्य स्थानो पर अपनी दुकाने खोल रहे है। महाराष्ट्र सरकार का भाव पहले 560 रुपये था फिर सौ रुपया बढ़ा दिया। वह 650-670 हो गया, मगर उन्होंने वहा 950 भाव लगा दिया। अब किसान तो देखता है कि जहा चार पैसे ज्यादा मिलते है, वहा चला जाता है।

उपसभाध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं-- आप और हम उसी स्टेट मे आते है, वहा कितना भ्रष्टाचार हो रहा है कपास में.... **(व्यवधान)**

डा० बापू कालदाते : आपकी स्टेट मे ना।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : किसानो के साथ पुलिस के लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे है। दस रुपये प्रति क्विंटल ले रहे हैं।... **(व्यवधान)** नही, नही बापू वह भ्रष्टाचार आन्ध्र प्रदेश मे हो रहा है। हमारे लोग उधर कपास लेकर के जा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश की जो सरकार है और जो उनके पुलिस वाले है, वह हमारे किसानो को लूट रहे है, भ्रष्टाचार वह कर रहे हैं। .... **(व्यवधान)**

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : आप जानते हो कुछ? आपको जानकारी है कुछ? आप बगैर जानकारी के कुछ कहो नही, अपनी जबान मत खोलिए। ... **(व्यवधान)**

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मै आपका नेबरर हू। आप बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बाते मत कीजिए। आपके वहा क्या कर रहे है, वह मै सब जानता हू।... **(व्यवधान)** हमारी जो कपास उधर जा रही है, तो उन्होने सारी दुकाने खोल रखी हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : [Only three minutes. You see, there is rationing of time! Just three minutes only.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : अभी तो मै बोलने के लिए खडा हुआ हूं। आप क्यो टाईम मे पाबन्द कर रहे है? मेरे तीन मिनट तो इंट्रप्शन मे गये है। तो बार्डर में जो दुकानें खुली हैं, उनमें काफी भ्रष्टाचार व्यापारी कर रहे है, वहा की पुलिस कर रही है, फिर भी किसानों को जरा ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसलिए किसान उधर कपास लेकर जा रहे हैं।

तो मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि अभी सारे देश में कपास का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ है इसलिए सौ रुपया तो भाव बढ़ा दिया है और सौ रुपया बढ़ा देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि किसान अपना कपास उधर नही ले जाए और यह जो काटन फैडरेशन स्कीम बनाई है, वह हमेशा के लिए चलती रहेगी।

उसके साथ-साथ, यह काटन मानोपली स्कीम की और एक समस्या है और उसके लिए सिर्फ 1990 तक मेरे ख्याल से एक्सटेंशन मिली हुई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दस साल के लिए एक्सटेंशन मागा था। तो मै आपके माध्यम से सरकार से रेक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यह जो काटन मानोपली स्कीम है, उसको दस साल का एक्सटेंशन मिले और किसानों का जो एक्सप्लायटेशन होता है व्यापारियों के जरिए, तो सारे देश में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जैसे हमारी रोजगार योजना इम्पलायमेंट गारटी स्कीम एडाप्ट की है, वैसे ही एक काटन मानोपली स्कीम पजाब में, गुजरात में, आन्ध्र प्रदेश में, जहां भी काटन प्रोडयूसिंग स्टेट्स हैं, वहा पूरी स्टेट में काटन मानोपली स्कीम एक्सटेंड किया जाये और किसानों को रहात दी जाए।

दूसरी बात यह है कि जब हम वित्त विधेयक पर बहस करते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यह तो एस्टिमेट है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कुछ दस मिलियन टंस

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

तक कम हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं मानता। जब मार्च में फिगर्ज आयेंगे, तो मुझे बड़ा विश्वास है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 145–150 मिलियन टन तक जरूर हो जाएगा, क्योंकि दो स्टेट्स में स्नियर सूखा है, मगर क्राप्स काफी अच्छी है। हां, पीने के पानी की समस्या है, चारे की समस्या है तथा सारे देश में इम्प्लायमेंट की समस्या है, मगर क्राप्स कुछ अच्छी है।

तीसरी बात यह है कि हमारी सरकार ने जो इरिगेशन की नीति अपनाई है, आज तक जो हमारे डैम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके है, उनका हमें काफी फायदा हो चुका है। ड्राऊट के बावजूद भी इरिगेटिड एरिया में हम अच्छी तरह से खेती कर सकते है।

सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में आयल सीडस की है, जिसमें आप भी बहुत इंटेस्ट लेते है। आयलसीड्स का प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ना चाहिए। उसमें कोई दो राय होने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत लज्जा लगती है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश होते हुए भी, हर साल हमें 7–8 सौ या 1500 करोड़ का एडिबल आयल बाहर से लाना पड़ता है। किसान को अच्छा भाव दीजिए, किसान के ग्राउडनट के लिए। अगर 5–6 सौ के बजाए आठ सौ रेट दिया जाए–मार्केट में अभी आप तेल की कीमतें देखते हैं, तो तीस रुपये किलो से बढ़कर है। एक किलो ग्राउडनट से तकरीबन चार सौ ग्राम तेल निकलता है, 350–400 ग्राम तेल निकलता है। उसका मतलब यह है कि 40–45 परसेंट आयल है। तो जब किसानों की जो मूंगफली मार्केट में देते है व्यापारियों की तरफ जाते हैं, तो उसके भाव बढ जाते है जब किसान के पास होती है, तो चार सौ रुपये क्विंटल से वह खरीदी जाती है।

तो जैसे काटन मानोपली स्कीम निकालने की बात—अगर वह स्कीम नहीं रहती थी, तो कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के बाहर से तीन चार सौ रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा कोई व्यापारी कपास नहीं खरीदते थे। (समय की घंटी) इसका जो यश है, वह काटन मानोपली स्कीम का है। उसी तरह से जो आयलसीड्स का उत्पादन हमने करना है, तो किसानों को प्राइसेज बढ़ाकरके दीजिए और उसको कुछ सहूलियतें दीजिए, फर्टिलाईज़र्स दीजिए, तो हमारा किसान 1500 करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेंज आपको मिला कर देगा आयल सीड्स से।

हमारी जमीन में इतनी ताकत है, हमारी मिट्टी में इतनी ताकत है और वह ताकत हमने नहीं देखी जिसे अकेला किसान ही समझता है। लास्टली, मैं यह कहना चाहता हूं उप सभाध्यक्ष जी, कृषि उद्योग के बारे में हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत ध्यान दिया है और अब हम देखते है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा सूखा राहत के काम में जा रहा है और एग्रीकल्चर में भी ज्यादा पैसा सरकार लगाने के बारे में सोच रही है और मैं इस सदन में प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी का अभिनन्दन करता हूं कि पहली बार इन्होंने देश में बहुत अच्छी तरह से किसानों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ... (व्यवधान) तो बात ऐसी है तो वह हमारे सामने जैसा आपने अलग-अलग पालिसी के बारे में कहा, अलग कृषि की पालिसी हमको बनानी चाहिए और जब तक कृषि को हम उद्योग के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कृषि उद्योग को आर्थिक और सामाजिक न्याय कुछ नहीं मिल सकता। हमारी अधिकतर जनसंख्या, 75 प्रतिशत पापुलेशन कृषि पर आधारित है और उसका जो जी डी पी है वह 34 कहते हैं, वह तो आर्टीफिशियल बात है सारा जी डी पी कृषि का ही है। मगर वह जो हमारी कपास है वह जब कारखाने में जाती है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाती है, हमारे जो फल है वे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो उद्योग का उत्पादन हो जाते है वैसे तो एग्रीकल्चर का टोटल जी डी पी 70 टू 80 परसेंट है, मगर हमारे जो अर्थशास्त्री ऊपर बैठे है उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। तो जब तक हम अपने नियोजन का 70 परसेंट अमाउन्ट एग्रीकल्चर को एलोकेट नहीं करेंगे तब तक एग्रीकल्चर को

आर्थिक न्याय नही मिलेगा । इस बात पर सोचने की जरूरत है। मैं चाहता हू सरकार ऐसी नीति अपनाए कि हमारे पास कृषि की एक पालिसी हो जाए नेशनल एग्रीकल्चरल पालिसी कृषि मूल्य की पालिसी हो जाए, जैसे मेरे मित्र श्री कल्पनाथ राय और हमने उठाया था कि एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन हम एक साल पहले डिक्लेयर कर चुके है मगर वह कभी आता ही नही, क्यों ? क्योंकि उसमें कृषि के जो दो मैम्बर है वे हम एप्वायंट करते ही नही है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स है वे नही चाहते कि उसमे किसानो के सदस्य आ जाए और उनको अगर ज्यादा भाव मिलने लगे, उनको ज्यादा प्राइस मिलने लगी तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो यह बात आप खत्म कीजिए और हमको अपने सोचने का ढंग बदलना चाहिए। सोचने का ढग जरा ब्यूरोक्रेसी से पालिटीशियन की तरफ आना चाहिए तथा कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन नियुक्त होना चाहिए उसमें 70 परसेंट प्रतिनिधित्व किसानो का चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का कुछ नही चाहिए, यह मेरी मांग है । उप सभाध्यक्ष महोदय, आपने तो टाइम की पाबदी लगा रखी है लेकिन मुझे तो बहुत कुछ कहना था । उप सभाध्यक्ष जी, इसके साथ मै एक और बात कहना चाहता हू अपनी स्टेट के बारे मे, हमारे महाराष्ट्र के करीब-करीब 42 इरीगेशन प्रोजेक्ट्स केन्द्र में पड़े हुए है । उनका अभीतक सेक्शन नही मिला । महाराष्ट्र की टोटल इरीगेशन कैपेसिटी अगर हंडरेड परसेंट प्रोजेक्ट पूरे किए तो वह 30 परसेंट तक जाती है और आज हमारी इरीगेशन कैपेसिटी 12 से 13 परसेंट है। तो मै आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हू कि जो प्रोजैक्ट्स सेक्शन के अभाव मे पडे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द क्लीयर किया जाए और हमारे राज्य का जो 1/3 भाग है वह परमानेंट ड्राउट जोन मे जाता है । इस परमानेंट ड्राउट जोन मे ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, इसकी हम व्यवस्था करे और सरकार उसके बारे मे अधिक ध्यान दे। इसी के साथ मैं सरकार का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हू । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) डा० बापू कालदाते ।

डा० बापू कालदाते उपसभाध्यक्ष जी, मै शुरू मे ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय आपत्ति मे हम आज तक आपके साथ रहे है और साथ रहेंगे यह वायदा सिर्फ किया ही नही बल्कि आज तक उसको पालते भी आए है । जो हम बोलते है वह हम करते भी हैं । इसके लिए मुझे इसमे कोई आपत्ति नही है कि सरकार अगर सूखा राहत के लिए अधिक धन का संचय करना चाहती है, मैं मानता हू कि यह आवश्यक भी है । लेकिन जिस ढंग से सरकार इन बातो को करना चाह रही है उसमें सदन की मर्यादा को और सदन की गरिमा को धक्का लगाने का प्रयास इस सिलसिले मे 1980 से जारी है । इसका मैं कड़ा विरोध करता हू । मैं यह मानता हू कि कोई भी टैक्स या कोई भी धन की जो कुछ भी कार्यवाही आप करते है यह सभी की सभी सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स मे जानी चाहिए, और जहा तक इसका सवाल है, आपने इस विधेयक के जो उद्देश्य और कारण है, उसमे बिल्कुल स्पष्ट कहा है –

"In order to raise resources for providing relief to drought affected farmers and persons in rural areas, the Government decided to levy. "

यानी आपने मतलब साफ कर दिया है कि यह विधेयक, यह आर्डिनेन्स जो निकाला है राष्ट्रपति जी ने वह सिर्फ इस काम के लिए निकाला है कि जो आज सूखाग्रस्त इलाके है इन सूखाग्रस्त इलाको के लिए आपको मदद करनी है । इसमे दो-तीन सवाल पैदा होते है क्योकि अध्यादेश तभी निकल सकता है, कोई ऐसी स्थिति हो, जिसकी कल्पना नही कर सकते और कोई अचानक बात हो जाय यह सदन उस समय उपस्थित न हो । तो क्या सरकार इतनी दुर्लक्षित रही कि सूखे के बारे में सितम्बर तक उसको पता ही नही लगा कि सूखे के लिए धन की जरूरत होगी ? क्या सूखा है यह मालूम नही था ? यह तो जून-जुलाई मे चल रहा था, जब खरीफ का पहला मौसम आता है मानसून आता है, तभी से पता हो जाता है । यह तो पहले से चल रहा था, जून से इसकी जानकारी थी,

[श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव]

अगस्त 28 तक पार्लियामेंट चला, सितम्बर तक हम लोग रहे । अब अगर सरकार यह कहे कि हमारी नजर मे यह आया हो नही तो मै इसके लिए कहूंगा कि सरकार के दुर्लक्ष का यह एक अप्रतिम नमूना हो सकता है । जो सरकार ड्वेचुअल्टी आने वाली है सूखे से, उसको नजर न आए, वह देख न पाए तो ऐसी सरकार को क्या कहूं, मै शब्द इस्तेमाल नही करना चाहता, लेकिन ठीक नही है यह, इतना तो खुद आप भी कहेंगे कि ठीक नही है कि सितम्बर तक आप चुप बैठे रहें । यह एक ऐसा सिलसिला है, जिसका मैं कड़ा विरोध करना चाहता हूं ।

महोदय, यह नई बात नही है । सरकार सन् 1980 से लेकर आज तक लगातार जब से आई है, जब-जब बजट के मामले आए है, उसक पहले कुछ-न-कुछ करती रही है । जैसे बजट आने के पहले कूड-आयल के दाम बढ़ा दो, बजट आने के पहले 10 परसेंट रेलवे का फेयर बढ़ा दो या कुछ ऐसा और कर दो ताकि आप दुनिया को यह दिखाने का प्रयास कर सको कि हमारा डेफिसिट कम है । प्राइसेस आप एडहोक ढग से बढाते रहेंगे और यहां दिखाने का प्रयास करेंगे डिफिसिट कम है । तो यह रास्ता ही गलत है । मैंने आपका जवाब पढा है, जब पार्लियामेंट मे एच० एम० पटेल साहब ने इस मुद्दे को उठाया तो आपने उनको कहा-क्या आप फाइनेन्स में मेक्रेटरी नही थे, तब यह करना नही पड़ता था । मै यह नही कहता हूं कि करना नही पड़ता है, लेकिन कौनसी अवस्था मे करना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए खासकर जब पैसे का मामला आता है ।

महोदय, माग कितनी है, 240 करोड़ की माग है और टोटली 550 करोड़ की बात है । मुझे अभी तक इस बात का पता नही लगा है कि सरकार ने, जिसको सरकार इस शतक का सबसे बुरा सुखाढ़ कह रही है, इस सूखे का अदाज क्या किया है, इसका आपका क्या असेसमेंट है, कितना पैसा लगने वाला है, कितनी क्षति हुई है और इसके परिणाम आगे क्या होने वाले हैं, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लगा है । किसानो को एक साल का सूखा तीन साल के लिए भुगतना पड़ता है क्योंकि एक साल सूखे का चला जाता है, कुछ राहत हम लोग इधर-उधर से दे देते है और उसे अगले साल वसूल करने का प्रयास करने लगते है । तो मुझे इस बात का दोहरा अंदाज चाहिए कि सूखे में आपका कितना पैसा लगने वाला है और दूसरा, इसके आगे क्या परिणाम होने वाले है ।

महोदय, मै इस अमेडमेंट को स्वीकार नही करना चाहता हूं क्योंकि यह सरकार का जो रवैया है, जो सिलसिला है, इस सदन की मर्यादा को भग करते चलना, इस सदन की गरिमा को धक्का लगाते चलना, यह ठीक नही है । इसलिए मै सर्वप्रथम इसके लिए जो हमारी शक्ति है, उस सारी शक्ति के साथ उसका मुकाबला करना चाहता हू और खासकर मैं सरकारी दल के जो लोग है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि यह कोई विरोधी दल का सवाल नहीं है, सदन हम सब लोगों का है, सदन की गरिमा, सदन की प्रतिष्ठा, सदन की मर्यादाओं का हम सबको ध्यान रखना है । इस सदन की मर्यादाओं को सजग और सशक्त बनाना हम सब लोगों का काम है । इस सरकार को अगर इजाजत दी तो शायद दूसरी सरकार इससे भी ज्यादा खतरनाक निकल सकती है । अगर इसके बारे में सजग नहीं रहेंगे सदन की मर्यादाओं के संबध में, तो मै समझता हूं कि सदन के हाथ में कुछ भी शक्ति नही रहेगी । एडहोक सब डिसीजन सरकार लेती रहेंगी और बाद में सदन में रखती रहेगी कि हम बहुमत वाले है, हाथ उठाकर या बटन दबाकर उसे मान्य करते रहेंगे और अल्पमत वाले सिर्फ विरोध करते रहेंगे । मैं इस बात को नही मानता कि सदन की मर्यादा का भंग किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्षमा-योग्य बात है । यह अक्षम्य बात है कि यह सरकार बार-बार इसी बात को अपना रही है । इसके लिए मै कड़ा विरोध प्रकट करता हूं ।

दूसरी बात जिसकी मुझे बहुत नाराजगी है वह यह है कि सूखा कोई आज नही पड़ रहा है । पिछले चार साल में मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक सूखे की बात चली है । लेकिन जिस ढग से आज सरकार

जाग उठी है वह गए तीन सालो मे क्यों नही जागी। क्या महाराष्ट्र के लोगो ने यह माग नही की थी कि हमे 400 करोड़ रुपए चाहिए। मुख्य मत्रीजी ने कहा था कि 400 करोड चाहिए। लकिन दिए सिर्फ 40–50 करोड़। क्या गजरात से लेकर नीचे वाले इलाको मे यदि सूखा पडता है तो कोई चिता की बात नही है? जब उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ेगा तभी चिता करने की बात हो जाती है।

श्री शरद यादव (उत्तर प्रदेश) : यह कही भी चिता नही करते।

डा० बापू कालदाते : मैं यह मानता कि सूखा एक राष्ट्रीय विपत्ति है लेकिन हम बहुत बार चिल्लाते रहे और आज भी चिल्लाते है दो साल से हम मांग कर रहे हैं कि कोई सेंट्रल टीम या मिनिस्टर वहा का दौरा करे। लेकिन वह गए नही और जब महाराष्ट्र मे थोडी-बहुत बरसात हुई तो सुब्बराम जी वहां गए। वे बरसात के बाद वहां पहुंचे। तीन साल सूखा पडा, लेकिन कोई सेंट्रल मिनिस्टर वहा नही जा सके। इससे हमको बड़ा दुख होता है। इस संबध मे म दो-तीन सुझाव दूगा। एक तो मेरा सुझाव यह है कि यह तो राष्ट्रीय विपत्ति है, लगातार चलने वाली विपत्ति है। इसके लिए मेरा यह सुझाव है और कुछ और माननीय सदस्यो ने भी सुझाया था कि आप राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक पर्मानेंट व्यवस्था कीजिए ताकि सर्वदल के लोग इसमें शामिल होकर सूखे और बाढ़ की मानिटरिग करे और उसका जो पैसा इकट्ठा हो वह ठीक ढंग से राज्यो को मिलता है या नही इसके बारे में इकट्ठे बैठकर विचार करें। दूसरे मैं ज्यादा अर्थशास्त्र तो नही जानता। लेकिन अविकसित और विकसित देशों में जो भी कुछ बाते करनी पड़ती है वह करे। एक तो मनुष्य शक्ति का मोबालाइजेशन—Manpower is the real capital for this country.

इस शक्ति का इस्तेमाल करें। दूसरी बात है सेविंग। Taxation is a part of savings. I agree with taxes which are needed for this country. तीसरी बात जिसकी तरफ मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं वह है कि जो खर्चा होना है, उसकी तरफ हम लोग ठीक से देखते नही है। मैं इसकी ज्यादा मिसालें नही देना चाहता हूं। मैं यह जरूर कहना चाहता हू कि जिस ढग से नान प्लाड और जिस ढग मे घृणास्पद प्रदर्शन संपत्ति का इस देश मे चल रहा है, वह ध्यान देने योग्य है। अब इस देश में दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक की जो शादिया की गयी तो ग्वालियर की शादी is a national disgrace. It is a historical disgrace. यह लाछन है क्योकि एक तरफ आप सूखे की बात करते रहे और दूसरी तरफ सादगी का संदेश हमको देते रहे कि सादगी का जीवन बिताए 'Austerity for us and luxury for you.' यह तो नहीं चलेगा।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : ग्वालियर की शादी का जो निमंत्रण पत्र हम लोगो को मिला था, उसमें लिखा था कि भोजन नही मिलेगा।

DR BAPU KALDATE : That is the fun of it.

मतलब यह है कि कुछ मिलेगा नही लेकिन सारी व्यवस्था हो जाएगी। मैं तो नही गया, इसलिए मैं नही कहूंगा कि हुई या नही। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इतने बड़े सूखे से हम ग्रस्त हैं त्रस्त है और बार बार प्रधान मत्रीजी हम लोगों को कहते हैं कि सादगी का जीवन बिताएं। कुछ और सदस्यों ने दो-तीन उदाहरण दिए हैं। मैं उसमें नही जाना चाहता। मैं कोई पर्सनल वे में बात नही कह रहा हूं। माधवराव जी और कर्णसिह जी हमारे मित्र हैं। लेकिन जब तक हम लोग जो इस देश की नेतागिरी करते है, उनके जीवन में जनता सादगी नही पाएगी तब तक न तो हमे कहने का कोई अधिकार है और न उसका जनता अमल करेगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से यह कहना चाहता हू और सुझाव भी देना चाहता हूं कि अगर आप इस देश में चल रहे घृणास्पद प्रदर्शन बंद कर सकें तो बडी मेहरबानी होगी। अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसके और कुछ असर होने वाले हैं। इसका कुछ और असर होने वाला है। आप जानते हैं कि

[डा० बापू कालदाते]

देश में जो अनाज का भडार है उस मे आप सूखे के भागो में अनाज देने वाले है। हम उसी पर भरोसा रख कर चलते थे। वह अनाज का भंडार निश्चित रूप से कम होने वाला है। तो तुरन्त ही उस भंडार को पूरा करने की व्यवस्था नही हो सकेगी। मुझे डर है कि अगर अनाज का भडार कम हो जायेगा तो अनाजो मे मूल्य-वृद्धि की सभावना है और अगर मूल्य वृद्धि होती है तो आप ने जो डेफिसिट बजट बनाया है उसमे और बढ़ोत्तरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस दिशा में, अनाज के भंडारण के संबंध में और घाटा जो है उसको आप मर्यादित रखे। जो 6000 करोड़ की बात है उस बारे मे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उस से और आगे न बढ़े इस के लिये सरकार को पहल करनी होगी और इस के लिये आप क्या कर रहे है, यह मैं जानना चाहता हू।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार जो वित्त (संशोधन) विधेयक, 1987 लायी है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

ग्रामीण क्षेत्रों मे सूखा से प्रभावित किसानो और व्यक्तियों को सहायता देने के लिए साधनो को जुटाने के लिए सरकार ने कुछ कर दाताओ पर पाच प्रतिशत का अधिभार उदग्रहीत करने का विनिश्चय किया है। क्योंकि संसद सत्र मे नही थी और अतिरिक्त साधनो को जुटाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक था, इसलिए वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1987 नामक अध्यादेश 19 सितम्बर, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

इस अध्यादेश के द्वारा वित्त अधिनियम, 1987 की पहली अनुसूची के भाग 3 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में जिसकी पचास हजार रुपए से अधिक की कुल आय है, जो अग्रिम कर का सदाय करने के लिए दायी है या जिसकी आय "वेतन" शीर्ष के अन्तर्गत कर के लिए प्रभार्य है, पहली अनुसूची के भाग 3 के उपबंधों के अनुसार परिकलित आय-कर की रकम मे ऐसी आय-कर के पाच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा सघ के प्रयोजनो के लिए वृद्धि की जाएगी। अध्यादेश मे यह भी उपबंध किया गया था कि ऐसे अग्रिम कर की किस्तो की बाबत जो 15 जून, 1987 और 15 सितम्बर, 1987 को संदत्त की गई थी, या संदेय थी, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार 30 सितम्बर, 1987 को या उसके पूर्व सदाय किया जाना था।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय सरकार ने एक विशेष परिस्थिति मे जब देश में सूखे और बढ़ का प्रकोप आया उस वक्त जो समाज के 50000 से अधिक कर देने वाले व्यक्ति हैं उनपर सरचार्ज लगाया है। विरोधी दल के नेताओं से मेरी यही प्रार्थना है कि राष्ट्र पर जब सकट का कोई पल आता है, जब पूरे राष्ट्र का जीवन संकट में पड जाता है तो ऐसे कदम का हर किसी को समर्थन करना चाहिए। एक माव निगेटिव एप्रोच रखना कि जो सरकार करेगी हम उसका विरोध करेंगे, आज विरोधी दलों का ऐसा ही दृष्टिकोण बनता जा रहा है और यह दृष्टिकोण बड़ा ही जनघाती है।

श्री शरद यादव : सिंधिया जी की शादी के बारे मे क्या विचार है आपका ?

श्री कल्पनाथ राय : हमारे मित्र डा० बापू कालदाते राष्ट्रीय विचारो के व्यक्ति है और मै उनके विचारों का विरोधी नहीं हूं। लेकिन मैं आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र के जीवन में कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं। हिन्दुस्तान एक विकासशील देश है। विकासशील देश की कुछ अपनी समस्यायें होती हैं।

[उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) पीठासीन हुए।]

उसमे सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष के लोगो को राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर उन समस्याओ का हल ढूढना चाहिए। आदरणीय वित्त मंत्री जी, आपसे मुझ यही निवेदन करना

है कि हिन्दुस्तान 1947 के बाद, जब इसको आजादी मिली, उसके बाद से आज तक हम सात पंचवर्षीय योजनाओं के दौर से गुजर चुके है । मेरा निवेदन है कि बाढ और सुखाड़ की समस्याओं को हल करने के लिये एक राष्ट्रीय नीति बनायी जाए और आठवी योजना, जो सरकार बनाने वाली है उसमे बाढ़ और सुखाड़ को प्राथमिकता दी जाए कि हिन्दुस्तान मे इस समस्या को कैसे हल किया जाए ।

सबसे पहला सवाल है वाटर मैनेजमेंट का । 1160 मिलीमीटर पानी हिन्दुस्तान मे बरसता है । इसमे से करीब करीब 50 प्रतिशत पानी नष्ट हो जाता है । एक ही प्रान्त के कुछ इलाके मे बाढ़ होती है और उसी प्रान्त के दूसरे इलाके मे सुखाड़ होता है । यदि हम पानी का अच्छा मैनेजमेंट कर दे तो हम बाढ़ और सुखाड दोनों की समस्याओं से निपट सकते है । इसलिए मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि 8वी पंचवर्षीय योजना में जो लोग टर्म पर्सपैक्टिव हो, जो आब्जेक्टिव हो, जो हमारी नेशनल प्रायोरिटी हो, जो राष्ट्रीय उद्देश्य हो, उसमें बाढ़ और सुखाड़ को प्राथमिकता दी जाए।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि यूरोप की जो इकानोमी है वह इंडस्ट्रियल इकानामी है । पूरे यूरोप का विकास शहरीकरण और औदयोगीकरण की उन्नति से हुआ है । लेकिन हिन्दुस्तान जैसे विकासशील देश की इकानामी की बुनियादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और हिन्दुस्तान की खेती की व्यवस्था है ।

महोदय, आजादी से पहले हमारे देश मे जो गावों मे खेती होती थी, उसमे छोटे-छोटे किसान अपने बैलों से खेत जोतते थे । खाद के लिए उनके गोबर का इस्तेमाल करते थे । सिंचाई के लिए अपने कओं का इस्तेमाल करते थे, रहट से सिंचाई करते थे बनिहार कटिया व बैलों के माध्यम से खेतों की मुडाई करते थे । इस तरह की उनकी अर्थ-व्यवस्था थी । लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति मे अब छोटे और मझोले किसानो को अपनी खेती के अंदर पैसा लगाना पडता है । यदि उसके पास 8 बीघा, 10 बीघा, 12 बीघा या 18 एकड़ भी जमीन हो तो उसको अपने खेत में ट्रेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है । सिंचाई के लिए नहर या ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना पड़ता है । बढ़िया फसल के लिए फर्टि-लाइजर यूरिया, अमोनिया, इंसेक्टिसाइड्स और पैस्टीसाईड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है । कोआपरेटिव बैंको और सरकारी बैंको से कर्ज लेकर वह अपनी खेती करता है । जब उसकी खेती लहलहाती है तो अकस्मात बाढ आने से उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है, या सुखाड आ जाता है तो उसकी खेती नष्ट हो जाती है और जो हजारो हजार रूपया कर्ज लेकर उसने खेती की है वह बरबाद हो जाता है । आज हमारे करोड़ों करोड किसान जो बिना कर्ज के खेती किया करते थे आज कर्ज में डूबे हुए है । अपनी पुरानी अर्थ व्यवस्था में वे बाढ और सुखाड का शिकार होते थे । वे भुखमरी का शिकार होते थे, लेकिन कर्ज का शिकार नही होते थे । आज हमारे किसान बाढ, सुखाड के साथ ही कर्ज का भी शिकार हो रहे है और इसके कारण आज हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है । आज गावों मे खेती करने वाले लोग करोड़ो करोड़ की संख्या में गांव छोड़कर जा रहे हैं और शहरों की तरफ भाग रहे है । पहले जितने परसेंट लोग खेती करते थे आज उससे कम लोग खेती कर रहे हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है और वे गाव छोडकर शहरो की तरफ भाग रहे हैं और रिक्शा, स्कूटर या टैक्सी चालक बन रहे है । इसलिए हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने के लिए ग्रामीण इलाकों का चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास होना चाहिए । इसके लिए हमको इसकी सारी संरचना के संबंध मे बुनियादी ढंग से विचार करना पडेगा और 8वी पंचवर्षीय योजना मे वैज्ञानिक ढंग से बाढ और सुखाड पर नियंत्रण स्थापित करना होगा ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मै वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हू कि हिन्दुस्तान मे एक कमीशन की नियुक्ति की जाए और वह इस बात की जाच करे कि हिन्दुस्तान के 7 लाख गावो मे कितने प्रतिशत लोग कर्जदार है । अगर इसका सर्वे किया जाएगा तो मालूम होगा कि आज हिन्दुस्तान के 7 लाख गांवो में रहने वाले करोडों करोड किसानो मे से 90 प्रतिशत किसान कर्जदार हो गए हैं ।

[डा० बापू कालदाते]

क्योंकि बिना कर्ज लिए उनकी खेती नही हो सकती । बिना कोआपरेटिव बैंको से लोन लिए हुए उनकी खेती नही हो सकती और वे उनकी खेती बाढ़ और सुखाड़ का शिकार हर साल हो जाया करती है और वे कर्ज को नही चुका पाते है तो उनके विरुद्ध वारट जारी किए जाते है और वे गाव छोडकर शहरो की तरफ भाग जाते है, कलकत्ता, बम्बई चले जाते है । इससे एक तरफ हमारे शहरों का अर्बनाइजेशन हो रहा है, पापुलेशन ऐक्सप्लोजन हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण इलाके उजड रहे है । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हू कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि हमारे गाव न उजडे । पानी की व्यवस्था करना बहुत बडी प्रोब्लम है । वाटर मैनेजमेंट इज ए बिगेस्ट प्रोब्लम बिफोर द कंटरी । हमारी पानी ही दौलत है, पानी से ही बिजली पैदा होती है और बिजली से कारखाने चलते है, नहरें चलती है, ट्यूबवैल चलते है । हमारे देश मे पानी का भडार है । प्रकृति ने भगवान ने इस देश को बहुत पानी दिया है । बहुत सा पानी समुद्र मे चला जाता नदियो मे चला जाता है । नदियां हमारे विनाश का कारण बन न जायें इस समस्या पर बुनियादी चितन करना चाहिए ।

मै पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हू । मेरे जन्मकाल से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार बाढ़ और सुखाड के शिकार रहे है । मैंने कई बार निवेदन किया है कि टिहरी डैम का निर्माण किया जाए । तीन डैम करनाली डैम, भालू डैम, राप्ती डैम का निर्माण नेपाल सरकार से बात करके नही किया गया तो आने वाले सैकड़ो वर्षो तक बिहार, बगाल और उत्तर प्रदेश बाढ और सुखाढ के शिकार होते रहेंगे । आधा इलाका बाढ मे बह जाया करेगा और आधा इलाका सुखाड के कारण नष्ट हो जाया करेगे । मेरा सरकार से निवेदन है वित्त मत्री से मेरी प्रार्थना है और सभी राजनीतिक दलों से भी प्रार्थना है कि नेपाल से निकलने वाली घाघरा, शारदा, राप्ती के ऊपर भालू बाध करनाली बाध, पंचेश्वर बांध का निर्माण किया जाए । जो गंगा हिमालय से निकलती है उस पर टिहरी डम का निर्माण किया जाए । हिन्दुस्तान मे इस समय 45 हजार मेगावाट बिजली बन रही है । 22 हजार मेगावाट बिजली इस समय पचवर्षीय योजना में बनाने का हमारा उद्देश्य है । बिजली की जितनी हमारी मांग है उसका आधा हमारे यहां उत्पादन हो रहा है । पानी से जो बिजली बनती है वह सस्ती बिजली बनती है । अगर हमारी सरकार टिहरी डैम, पाचेश्वरी डैम, करनाली डैम भालू बाध का निर्माण कर दे तो 50 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते है । यह मेटना कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मे दिया है । सरकार से मेरा निवेदन है कि 8वी पच-वर्षीय योजना मे हाइड्रो-इलेक्ट्रीक जनरेशन को प्राथमिकता दे । बाढ और सुखाड मे देश को बचाने के लिये, देश को वैज्ञानिक ढग से विकसित करने के लिए इन नदियो पर डैम का निर्माण कराया जाये । इससे एक तरफ ऊर्जा मिलेगी और दूसरी तरफ बाढ की विभीषिका से बचाव होगा । जो नदियो मे ज्यादा पानी है उसका इस्तेमाल हम सुखाड मे बचाव के लिये कर सकते है । पूरे राष्ट्र का एक वाटर ग्रिड बना चाहिये । पानी किसी प्रदेश का नहीं है पूरे देश की सम्पत्ति है । जहा पानी की आवश्यकता है वहां पानी को वैज्ञानिक ढंग से पहुचाया जाए और बाढ और सुखाड़ से देश को बचाया जाए ।

वित्त मंत्री जी ने जो यह अधिभार लगाया है यह पूंजीपतियो पर लगाया है । पहली बार हमने देखा है कि सरचार्ज ऐसे वर्ग पर लगाया है जो पूंजीपति वर्ग है या समाज का बडा वर्ग है या देश का जिस के पास ज्यादा पैसा है उस पर लगाया है । 50 हजार से ऊपर आमदनी पर सरचार्ज लगाया है । यह समाजवादी कदम है और ऐसे कदम है की सराहना चारों तरफ से होनी चाहिये । बाढ़ और सुखाड़ राष्ट्रीय सकट है इसलिए हमे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए । विश्वास है कि हमारी भारत सरकार, हमारे वित्त

मंत्री जो अगली 8वी पचवर्षीय योजना बनने जा रही है उस योजना मे बाढ़ और सुखाड़ को प्राथमिकता देंगे ताकि देश के ग्रामीण इलाको का सात लाख गांवों को फायदा हो । ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम बढा सके यह हम चाहते है क्योंकि बिना ग्रामीण, अर्थव्यवस्था को बढाये हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत नही बना सकते । इन शब्दो के साथ मैं इस विनियोग विधेयक का समर्थन करता हू ।

श्री राम अवधेश सिह (बिहार) . माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मै श्री जमवन्त सिह जी के सकल्प का समर्थन करने के लिए और वित्त विधेयक का विरोध करने के लिए खडा हुआ हूं ।

महोदय, इस सरकार का जो आज तक का आचरण रहा है वह हाथी जैसा है । खाने के दात और, तथा दिखाने के दात और । जिस तरह हाथी के दिखाने के दात और होते है उसी तरह इस सरकार की बोलने की जुबान भी अलग होती है और कर्म मे दूसरी ही बात यह सरकार करती है । आज तक मुझे याद नही है कि कांग्रेस की हकूमत ने कभी भी जो वचन दिया उसका पालन किया । मै एक बात चुनौती के साथ कहना चाहता हू कि इस सरकार ने जो भी वायदा किया, बहुसंख्यक समाज के लिए जो भी वायदा किया उसको कभी भी पूरा नही किया । हा, यह सरकार कमीशन बनाने मे बहुत तेज है । कमीशन बनाती है, उस पर जनता की गाढी कमाई का पैसा खर्च करती है और उस कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसको गर्त मे डाल देती है । बहुसख्यक समाज की हिस्सदारी का जब सवाल आता है तो यह सरकार चुप्पी साध लेती है । सन् 1952 से, मै इसको नेहरू खानदान वाली सरकार कहता हू, नेहरू खानदान वाली सरकार हमेशा अल्पसख्यको, पिछडी जातियो, हरिजनों, आदिवासियो को ठगती रही है, महिलाओ को ठगती रही है । लेकिन सयोग से जो एक महिला प्रधान मत्री बनी तो आशा थी कि कुछ महिलाओ का उद्धार होगा, लेकिन वह भी नही हुआ । जब एक महिला हमारे देश की प्रधान मत्री बनी तो उस वक्त डा० लोहिया ने कहा था कि अब महिला हमारे देश की प्रधान मत्री बनी है, शायद अब महिलाओ का उद्धार हो, उन्हे चूल्हे-चौके मे जो आंसू बहाने पडते है वे आसू उनको न बहाने पढ़े । यह सोचा गया था कि अब महिलाओ को पाखाना, पानी और चूल्हे की परेशानी का सामना नही करना पडेगा । लेकिन वह भी नही हुआ, महिलाओ के आसुओ को नही पोछा गया । काका कालेलकर जी ने सन् 1955 मे अपनी रिपोर्ट दी । 22 साल तक वह रिपोर्ट यों ही पढी रही । पडित नेहरू लोगो को ठगते रहे, इदिरा गाधी ठगती रही और मोरार जी देसाई भी लोगो को ठगते रहे । आपको याद होगा, श्री मोरार जी देसाई ने अपने चुनाव घोषणा पत्र मे यह लिखा था कि काका कालेलकर आयोग की सिफारिश को लागू किया जाएगा । लेकिन उस आयोग की सिफारिशों को लागू नही किया गया । मैने इस सवाल को उठाया, सडक पर उठाया प्रदर्शन किये, बसो को जलाया, पोस्ट ओफिसिज को जलाया . (व्यवधान) ।

वित्त मत्रालय मे व्यय विभाग मे राज्य मत्री (**श्री बी०के०गढवी**) यह आपने बहुत अच्छा काम किया ?

श्री राम अवधेश सिह : भ्रष्टाचार को समाप्त करने लिए हमे सडको पर जान पडे तो जाएगे, बसो को जलाना पडे तो जलाएंगे . (व्यवधान) । श्री मोरार जी देसाई ने बयान दिया कि सरकार के सारे वायदे पूरा करने के लिए नही होते हैं । ऐसा निर्लज्जतापूर्ण बयान उन्होने दे दिया । हमने कहा कि आप भारत के प्रधान मत्री है, किसी विदेशी सरकार के प्रधान मत्री नही हैं, इगलैण्ड या पश्चिमी देशो के प्रधान मत्री नही हैं .... (व्यवधान) ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : वे तो आपकी पार्टी के थे, आप ही लोग उस वक्त पावर मे थे ।

श्री राम अवधेश सिह : हमने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई थी । हम अपनी सरकार के खिलाफ भी लड सकते हैं और आपकी सरकार के खिलाफ भी लड सकते है । जो भी नपुसक सरकार होगी जहा भी सरकार

[श्री राम अवधेश सिह]

गलती करती है, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। जब मेरी पार्टी की हकूमत थी तो मैंने मोरार जी देसाई को कहा था सौभाग्य से आप हमारे देश के प्रधान मत्री है अगर इग्लैण्ड, जर्मनी या पश्चिमी देशो के प्रधान मत्री होते और इस तरह से कहते कि वायदे पूरे करने के लिए नही किये जाते है तो आपको कान पकड़ करके एक मिनट में जनता हटा देती। तो इस तरह से काका कालेलकर कमीशन को झुठलाया गया है। सात साल से इस आयोग की रिपोर्ट पड़ी हुई है रोज कुछ न कुछ नयी बात की जाती है लागू करने के लिए। इस सदन मे और दूसरे सदन मे भी आश्वासन सरकार ने दिया, श्रीमती इंदिरा गाधी ने दिया।

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : समय आपको अधिक नही मिलेगा इसलिए आप अमेडमेंट पर ही बोलिये। वैसे आप जो बात कर रहे है वह विधेयक से सम्बन्धित नही है। आपका समय हो रहा है इसलिए मै आपका ध्यान दिलाना चाहता हू कि विधेयक पर आपको जो कुछ कहना है वह कहिये बाकी बाते तो आप कहते ही रहते है।

श्री राम अवधेश सिह : यह भी कहने दीजिये और वह भी कहने दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : इस तरह से ही नही पाएगा। जो प्रमुख चीज है वह आप कहिये।

श्री राम अवधेश सिह : जो प्रमुख चीज है, वह कहने दीजिये **(व्यवधान)**

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab) : He takes all the time on preliminaries osly.

श्री राम अवधेश सिह : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार पिछडे वर्गों को, हरिजनो को, आदिवासियो को माइनार्टीज के लोगो को ठगती रही है और मै कहना चाहता हू कि अब ठगने का काम चलने वाला नही है। अब खत्म हो गया है, अब समय आने वाला है, हम आपसे इसका सडक पर जवाब पूछेगे, हम आपसे इसका सडक पर जवाब पूछेगे और आपको जवाब हमको देना होगा। हम आपको यह बता देगे कि किस तरह से वायदा-खिलाफी का क्या परिणाम होता है **(व्यवधान)** अब मै कुछ बिहार के बारे मे कहना चाहता हूं। बिहार को केन्द्रीय सरकार लूट रही है। इन्होंने इकोनोमिकली बिहार को लूटा और राजनीतिक ढग से भी लूट रहे है। इकोनोमिकली यह इस तरह के कानून बनाते है फ्रेट इक्वीलाइज़ेशन करते है यानी जिस रेट पर इनको लोहा कोयला, बोकारो धनबाद मे मिलेगा उसी रेट पर यह गुजरात में पहुचाते है, उसी रेट पर अहमदाबाद मे पहूचाते है, उसी रेट पर हरियाणा और पंजाब मे पहुचाते है जहा तक किलो भी कोयला न निकलता है, न लोहा निकलता है, वहा उद्योग-धन्धे सबसे ज्यादा है। उनकी पर-कैपिटा इनकम चार हजार रुपये है और हमारे यहां जहां पर सारे देश के 45 प्रतिशत खनिज सम्पदा के रिज़र्व पड़े हुए है हमारी पर-कैपिटा आमदनी सबसे कम है, नागालैन्ड से भी कम है। औसत भारतीय इनकम से भी कम है। तो यह इनकी नीति चलती है कि बिहार को लूटा जाए और दूसरे राज्यो को बनाए जाए। यह बात अब चलने वाली नही है। पोलिटिकली कैसा लूटा है **(समय की घटी)** बिहार के कम से कम तीन कैबिनट मिनिस्टर हुआ करते है केन्द्र मे और चार पाच स्टेट मिनिस्टर हुआ करते है। अब इस वक्त तीन तो माख्आ कटुआ स्टेट मिनिस्टर है जिनमें कोई दम नही है लुज लुज है दम नहीं है उनको मत्री बनाकर केवल खाना-पूर्ति कर दी गई है उनको यहा बैठा दिया गया है एक भी दमदार आदमी मंत्री परिषद मे नही रखा है न कैबिनट मे न स्टेट मिनिस्टर के तौर पर जो कि यहा पर बिहार के बारे मे बोले और बिहार की हिस्सेदारी के बारे मे बोले। कोई भी काम ऐसा नही करते है जिससे बिहार के लोगो को लगे कि हमारा भी कोई इस राज मे हिस्सा है। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश के साथ जो यह हकूमत करते थे हमेशा सरकार बदलती थी पोस्टमेन की तरह से समझते थे वहा की हकूमत को तो उन लोगो ने यह बता दिया है कि हम लोगों को दिल्ली से कोई जरूरत नहीं है दिल्ली की हकूमत के अंकुश में रहेगे तो हमारा काम

नहीं होगा हम यह कहना चाहते है कि बिहार भी दिल्ली की हुकूमत से बाहर जाने वाला है । अगर इसी तरह से आर्थिक शोषण और राजनीतिक शोषण होता रहेगा तो यह अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (डा बापू कालदाते) : अब आपका समय हो गया है । आपको एक मिनट मे अपनी बात समाप्त करनी है । अब ज्यादा समय नही मिलेगा । आप सहयोग दीजिये ।

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal) : Sir, you are very unfair. You yourself said that drought does not have effect only for a year. Its impact is long-lasting. So he will take time.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDHTE): I have got your point.

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, जो सरचार्ज लगाया गया है, सारे राज्यों में लगभग सूखा पडा हुआ है इसका सरचार्ज का जो स्केल है यह 10 लाख, 20 लाख, एक करोड़ या दो करोड़ जिनकी आमदनी है, उन पर ज्यादा होना चाहिये । आपने यह जो रेंज पांच परसेंट का रखा है यह बहुत ही कम है । मै चाहता हूं आपका पजा वहां पड़ना चाहिये जहां खून या मांस कुछ हो सूखी हुई हड्डी पर 50 हजार, 60 हजार या एक लाख आमदनी कोई खास बात नही है । जिनके पास 10 लाख, 20 लाख या एक करोड़ या दो करोड़ की आमदनी है उनसे कुछ ज्यादा सरचार्ज लिया जाय 25 परसेंट लिया जाए तो क्या हर्ज है । आप जो ले रहे है 240 करोड़ वह लीजिये लेकिन मै तो यह चाहता हू कि आप 500 करोड निकालिये लेकिन यह जो आपने स्केल निश्चित किया है इसको आप बढ़ाइये । जहां तक सूखे का सवाल है नाबार्ड से 320 करोड रुपया बिहार सरकार को मिला है, सूखे का सामना करने के लिए मिला है । आपको जान कर आश्चर्य होगा कि उस रुपये का क्या हुआ बिहार में उसमें यह कह दिया गया है कि कोआपरेटिव के माध्यम से खाद दी जाएगी। इसके 40 फीसदी में आपको खाद दी जाएगी किसानों को रबी फसल बोने के लिए । खरीफ की फसल तो बाढ़ में मारी गई है कुछ सूखे के कारण मारी गई है लेकिन रबी तो ठीक हो जाए इसलिए आपको 40 परसेंट खाद लेनी पड़ेगी केवल विस्कोमान से **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : अभी आपको खत्म करना है । अब समय नहीं है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : अब तो असली बात कह रहे है उनको बोलने दीजिये ।

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : ऐसे कैसे होगा ।

श्री राम अवधेश सिंह : तो 40 फीसदी पैसा नाबार्ड का कोआपरेटिव्ज से खाद खरीदने के लिए दिया गया और वह खाद कैसी थी मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं । सन् 1982-83 मे खाद खरीद कर कोआपरेटिव्ज द्वारा विस्कोमान से दिया गया वहां पर विस्कोमान ने जो खाद सप्लाई की उससे किसानो की सारी फसल जल गई । खाद जो कोई रिकोग्नइज्ड कम्पनी है वहा से नही ली गई फर्जी कम्पनी जिसने बालू मे कुछ रसायनिक मिला कर दे दिया फिर उसकी जांच हुई और इस नतीजे पर पहुंचे कि किसानों को कम्पनसेशन दिया जाए लेकिन आज तक उनको कोई कम्पनसेशन नही दिया गया । विस्कोमान का चेयरमेन तपेश्वर सिंह राजो सिंह की कंपनी ने बिहार को लूट लिया अगर कोई दूसरा देश होता तो जो खाद डाल कर किसानों की फसल को सुखवा दिया तो उसको फांसी पर लटका दिया गया होता लेकिन बिहार के पांच जिलों में भोजपुर, रोहतास, नालंदा, औरंगाबाद, पटना, पांच जिलों की गेहूं जला दी गई 1983 में उसकी जाच भी हुई । मैं यह माग करता हूं कि अभी तक नाबार्ड का जो पैसा 40 फीसदी खाद के लिए दिया गया विस्कोमान से खरीदने के लिए क्या विस्कोमान से यह 40 फीसदी पैसे का खाद उठा या नही उठा इसकी जाच हो । मैं आज की तारीख में यह मांग कर रहा हूं हालांकि रबी बोने का मौसम अब नहीं रहा है समाप्त हो गया है लेकिन मैं सरकार से यह

[Shri Ram Awadhesh Singh]

चाहता हूं कि वह इस बात की जांच करे कि किसानो को अभी तक विस्कोमान से जो खाद खरीदनी थी कितनी खाद और कितना रुपया उस 320 करोड़ से इस मद पर खर्च किया गया है और कितनी खाद खरीद ली गई है। मै यह चुनौती देता हू कि इस मे से कम से कम 30, 40 प्रतिशत रुपया यह जो विस्कोमान के अध्यक्ष है बाबू तपेश्वर सिह और राजो सिह की जेब मे चला गया है। इस की संसदीय समिति के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। यह सरकार के ऊपर कलंक है। आप यहां से टैक्स लगा कर के पैसा ले लेते हैं और उस पैसे की लूट हो जाती है जब वह राज्यो में खर्च करने के लिए जाता है इसलिए आपको इस पर एक जांच बैठानी चाहिए और सदन को बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि जाच के बाद क्या हुआ। धन्यवाद।

1.00 P.M.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very happy that the Government has brought this Bill. In one of the meetings connected with direct taxes I had suggested that for the purpose of fighting the drought, we should raise resources. This was suggested by persons like me, that a surcharge should be levied on income-tax. My very good friend, Mr. Nirmal Chatterjee, supported at that time that we must mobilise resources. This was one of the measures which was suggested. I am happy that the Government has brought this At that time also we suggested that it should be such that small assessees should not be burdened. The Government has taken care and has levied the surcharge only on those whose income is more than Rs. 50,000. I am very happy about it

But one thing, I am not able to understand. Why are the NRIs and foreign companies exempt from this? This tax is on the amount of income-tax that they have to pay. The rate of tax has nothing to do with this. If the Government feels that the rate of taxes on foreign companies is less or different and that is why it is not taking them under the purview of the surcharge, I think, that is very wrong. They also should be included. The surcharge should have been levied on NRIs and also foreign companies because it is based on income. On the tax they have to pay, 5 per cent has to be paid.

I want to speak on three or four aspects. I am not going to make a lengthy speech regarding the taxation policy now, and I will speak on it when the Direct Tax Laws (Amendment) Bill is taken up.

The Government has committed another mistake which I would like to point out. They have reduced the rate of interest on the National Savings Certificates. From 12 per cent they have reduced it, I think, to 11.5 per cent. They have reduced it when the value of the rupee has gone down because of inflation. So, the real rate of interest they are getting now is not even 11 per cent. When the rate of interest was 12 per cent, even then, because of inflation, it was 11 per cent in real terms. Now it is 11 per cent. But in real terms the rate of interest is not more than 10.5 per cent. Who are affected? Who invest their money in the National Savings Certificates and other saving schemes? It is only those who are middle-class persons, salaried employees who save something. They put in this kind of deposit. You have robbed them of this benefit. That is why, I request the Government again that they should consider this. What has happened? Because of this, the fate of all the State Governments, especially the States of Maharashtra, Gujarat and West Bengal and other States is such that they are finding it difficult to get small savings' investments. Their resources are very small. The savings have gone down. That is why, they are finding it difficult to plan their budgets, they are having difficulties in planning. That is why, I again request the Government. Instead of reducing it, they should have increased it. Instead of giving benefit to small and middle-class assessees, you have put them to hardship. No industrialist puts his

money in small savings. He put it in industries. So, industrialists are not affected. They want that the advantages should be reduced. To give advantages to them, the Government has come forward with this very bad measure, to help the industrialists at the cost of the small assessees and middle-class families. This is a very wrong step. The Government should correct this wrong step. I request the Minister to ponder over this because, otherwise, all the State Governments and middle-class assessees will be affected.

Another thing which I would like to say is this. If the money supply is more, the price goes up—that is the economic theory. But, I don't believe in this economic theory I feel this way Even if there is an increase in the money supply, if the production goes up much more than the increase in the supply of money, the prices will not go up. That is why, we should not bother much about the increase in the money supply. We have see that the production of goods increases at a faster rate than the rate of increase in the money supply. That is why, I would request the Government to see that all industries are allowed to go according to their capacity which has been installed.

Shortage of power is the factor which has inhibited industries from going in for higher production. That is why the Government must see that power production is increased. From my studies I have found that the cost of nuclear energy and thermal energy production is more or less same That is why we have to go in a very big way for production of energy so that there is more production of goods enabling prices to come down. Because of this we will be able to see that effect of inflation in spite of the drought can be reduced to the minimum. That can be done only when the goods are produced at a very high scale.

Secondly, I would like to say one thing about the show of wealth I am vehemently opposed to this. Public men like us in particular must set an example before the people. Therefore, I would like the Government to ponder over the idea which I would like to put forth just now. Wherever there is marriage reception or any other kind of reception, prior notice at least of 15 days must be given so that the Income-tax officials can visit these places ot find out how much expenditure they are making on this. This will help curb black money which is being spent on these expenditures. That way wasteful expenditure on receptions etc. can be controlled.

श्री चतुरानन मिश्र : और मंत्री लोग हो, तब क्या ?

श्री जगेश देसाई : कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, यह जो समय है, जब हमारे देश मे इतना सूखा है, हमे समझना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए, हम सब को अनुशासन में रहना चाहिए और हमें इस प्रकार की जो फिजूलखर्ची है, वह चाहे डिपार्टमेंट मे हो, या कहा पर भी हो, हमे उसे खत्म करने का काम करना है ।

इतना ही कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हू कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री राम अवधेश सिंह : गेस्ट कंट्रोल समाप्त नही हुआ है ग्वालियर के राजा पर । ...(**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र : हमसे पूर्ववक्ता, माननीय सदस्य जगेश देसाई जी ने बहुत अच्छा... **व्यवधान**

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : आप भी बोले, तो इनको कौन सुनेगा ? उनकी बात सुनें ।

श्री चतुरानन मिश्र : अभी मुझ से पूर्व, माननीय सदस्य जगेश देसाई जी बोल रहे थे । उन्होने चर्चा की कि जो फिजूलखर्ची है, उसको रोका जाए, लेकिन जब सरकार के मंत्री ही करे, तो इसको कौन रोकेगा । सिपाही आकर के रोकेगा ।

मेरे पास अभी सूचना मिली है ग्वालियर से, जहां रेल मंत्री की लड़की

[श्री चतुरानन मिश्र]

की शादी हुई है। वह लड़की सौभाग्यशाली हो, संतानवती हो--मैं सब आशीर्वाद देता हूं, लेकिन प्रश्न यह है कि सरकारी रुपये का, सरकारी धन का जो दुरुपयोग होता है और वह अकाल के वक्त, सिर्फ अपने ही रुपये नहीं, जिसके लिए आप इनकमटैक्स की बात करते हैं, हमारे पास खबर आई है कि सवाई माधोपुर से ग्वालियर तक की जो रेल लाईन बंद थी, उसको अभी चालू किया गया है इस अवसर पर।

हमारे पास सूचना है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, उन्होंने माताटिल्ला से लेकर ग्वालियर तक स्पेशल कई करोड़ रुपया खर्च करके लाईन बिठाई। उन्होंने भोपाल से लाकर के पांच स्पेशल ट्रांसफार्मर्ज और 25 जेनरेटर्ज लाकर के इनस्टाल किये, चार सौ गाड़िया इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की वहां पर उनकी शादी के लिए दी गईं।

अब यह क्या गांधी जी की पार्टी रह गई है, क्या महात्मा गांधी को जिसको देखकर लोग आए थे इस दल में, अब क्या आपकी पार्टी भी इसकी जांच नहीं कर सकती है? क्या इतना उनका पतन हो गया है इस दल का कि अब इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है? हमको अत्यंत दुख है।

इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो यह रुपया ले रहे है, यह रुपये की बात नहीं है, मैंने तो एप्रोप्रिएशन पर बोलते समय भी कहा था कि और भी ज्यादा रुपया चाहिए तो राष्ट्र देने के लिए तैयार होगा। हमारी शिकायत है कि रुपये की आप फिजूलखर्ची करते हैं, बरबादी करते हैं। अब एक उदाहरण लीजिए, लोक सभा में मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि एक आई. टी. सी. कंपनी पर 1600 करोड़ रुपया कर का बकाया है। तो जब 1600 करोड़ रुपया उस पर बकाया रहता है तो आप इस पर किस बात कह रहे हैं, आज जब सुबुल जी बोल रहे थे बलिदान के बारे में जो मंदिरों में होता है तो हमको यह याद पड़ा उप-सभाध्यक्ष महोदय, कि जितना बलिदान आज गरीबों का आपके राज में हो रहा है इस बाढ़ में, सुखाड़ में और जो व्यवस्था है उसमें जो लोग मर रहे हैं उसको कोई देखने वाला नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने तो बहुत पहले से लिखा था, हमारे लोगों ने, आचार्यों ने, बाछ को बलिदान देने के लिए नहीं कहा, हाथी को बलिदान देने के लिए नहीं कहा, भेड़िये को नहीं कहा, बकरी के बच्चे को ही कहा है कि बलिदान दिया जाए, क्योंकि सब से गरीब वही था। वह मुकाबला नहीं करता। अगर यह लिख दिया जाता कि बाघ का बलिदान दिया जाए तो कोई नहीं देने के लिए जाता।

तो यह हमारे देव लोग भी दुर्बल का ही नाश चाहते हैं और यही यह सरकार भी कर रही है। अगर एक ही बात पर गारंटी मिले तो मैं सारी चीजों को छोड़ करके इस विधेयक का समर्थन कर सकता हूं। अगर यह सरकार आश्वासन दे कि बाढ़ और सुखाड़ के लिए कोई कालबद्ध योजना बना करके एक स्थायी समाधान निकाला जाएगा? एक-दो वर्ष में तो होगा नहीं चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ आश्वासन चाहता था कि अगर आप इसके लिए अगले बजट सत्र में व्यवस्था करें? कुछ माननीय सदस्य ने तारीफ की थी कि यह विदेश से सहायता मिली है। परन्तु हमको अत्यन्त दुख है कि 40 वर्ष की आजादी के बाद भी हमको कोई भीख दे और यह अत्यन्त ही लज्जाजनक बात है चाहे वह सहायता कहीं से भी आए, किसी तरह से भी आए।

श्री बी के गढवी: हम किसी के पास मांगने के लिए नहीं गए।

श्री चतुरानन मिश्र: अगर आपको बिन मांगे भी मिली है तब भी भीख ही तो है।

श्री बी के गढवी: लेकिन यह तो सहायता मिली है।

श्री चतरानन मिश्र : बेशक सहायता के लिए। लेकिन हमको इस शब्द का अर्थ बता दीजिए ? अब यह अलग बात है कि आप खाली बर्तन लेकर गए थे। हमको यह स्पष्ट ढंग से अपमानजनक लगता है कि 40 वर्ष के बाद भी हम सहायता लेंगे। हम इस परिस्थिति में आ गए है कि हम लोगों को सहायता दे। इसलिए हमने आपसे कहा है। फिर आप क्या करते है, वहां से जो 'तेल' मिलेगा उसको भी बेच देंगे। अगर मिला फ्री में तो यहां बेच देंगे। आपने बेच दिया। शायद उसी तरह से बेच दे। सरकारी खजाने में जाता। यह अक्शन कर देंगे। जो आक्शन में ले लेगा वह डयोढ़ा दाम लेकर बाजार में बेचेगा। जब हम कहने के लिए आयेंगे तो कहेंगे कि हमने तो अक्शन कर दिया। सरकार क्या करे। हमने तो आक्शन कर दिया। हमने तो डिस्ट्रीब्यूशन सेन्टर कायम कर दिया। यही तो हमारी नीति है। हमको इस बात से अत्यन्त दुख है कि आपको गोडउन में गल्ला सड़ रहा है लेकिन आप उसको गरीबी को नहीं देंगे। उनको काम में लगा कर नहीं देंगे। यह जो नीति है यह सबसे राष्ट्रघाती नीति है और इसी के चलते मैं आपका विरोध करता हूं। आपको एक उदाहरण दे दे। मैंने पिछले दिन कहा था कि 70 हजार करोड़ रुपया सिर्फ 209 प्रोजेक्ट्स के टाइम एसकेलेशन के चलते कास्ट एस्केलेशन हुआ था। उप सभाध्यक्ष महोदय उसमें होता क्या है कि यह जो काट्रेक्टर्ज लोग इस्तेमाल करते है वह जान-बूझ करके दूसरा एस्टीमेट बनाने के लिए, वे सब कांट्रेक्टर्ज जो हमारे पब्लिक सेक्टर के लोग भी एप्वायंट करते हैं वह खर्चा बढ़ाने के लिए तारीख बढ़ा दिया करते हैं, काम को समय पर पूरा नहीं करते है। अभी एन० टी० सी० के मजदूर आज दो महीने से धरना दिए हुए हैं हमारे एनर्जी मिनिस्टर के यहां कि भाई सब कांट्रेक्ट ऐसी स्थिति में दही कीजिए। समय पर काम पूरा किया जाय और हमको काम करने दीजिए। करोड़ों का मशीन आपने बैठा रखा है और जब वह कांट्रेक्टर को काम देते हैं तो इस तरह से भ्रष्टाचार में सारा रुपया डुबा देते हैं। इसलिए मैं इसके खिलाफ में हूं, एक रुपया आपको नहीं दिया जाए। अन्यथा अकाल की हालत में दिया जाए तो यह तो सब से जरूरी होगा। मैं दो-तीन मिनिट और समय लेना चाहता हूं आपका। आप देखिए, यह फर्टिलाइजर के लिए सबसिडी देते है। मैं कहता हूं, कोई फर्टिलाइजर के लिए सबसिडी की जरूरत नहीं होगी, अगर मंत्री जी हमारी बात का जवाब दें। यह जो आप गैस बेचते है, इससे फर्टिलाइजर बनता है। अमरीका में जो गैस का दाम है, उससे पांच गुना ऊंची कीमत पर गैस आप बेचते हैं। अगर पांच गुनी कीमत पर गैस बेची जाएगी तो फर्टिलाइजर महंगा होगा ही। उनका रिटेंसन प्राइस सिस्टम जो है, वह इतना डिफेक्टिव है कि अगर 80 परसेंट की कैपेसिटी होगी तो रिटेंसन प्राइस का लाभ मिलेगा। लेकिन 80 परसेंट केपेसिटी पर तो काम ही नहीं हो रहा है, काम हो रहा है 50–60 परसेंट पर क्योंकि आउट-मोडल प्लांट फर्टिलाइजर के आप ले आए है इटली से या दूसरी जगहों से और यहां खड़े कर दिए है। इसलिए कास्ट ज्यादा हो जाती है और आप हमसे कहते है कि सबसिडी देते है। आप अपनी नालायकीयत के दाम वसूलते है जो आप कहते ही नहीं है, उल्टे आप कहते है कि सबसिडी देते है। यह तो हमें आपकी नालायकीयत का दाम चुकाना पड़ता है, राष्ट्र को चुकाना पड़ता है।

महोदय, इसी तरह से हम लोग अगर देखें तो पाएंगे अपने देश की स्थिति जो आज है, पंजाब को आप सहायता देते हैं। ठीक है, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन तब तो एक ही अर्थ निकलता है कि अगर हम बंदूक उठाएं तो आप सहायता दीजिएगा, अगर हम अराजकता पैदा करें तो आप सहायता दीजिएगा। इस देश के अंदर एक बहुत विशाल भूभाग है, जो उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है, जो सबसे दरिद्र इलाका है, 20 करोड़ आजा का, सबसे लोअर पर कैपिटा इन्कम है यहां की, वहां आप कोई व्यवस्था नहीं करते है, तो क्या इस देश का कोई कल्याण हो सकेगा और जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, वह यह कि दुनियां के अंदर जो टेक्नीकल क्रांति आयी है, तरक्की हुई है, उसको आपको लाना चाहिए। आप कहते हैं कि मोडर्नाईजेशन करते हैं, इससे मेरा एतराज नहीं है, आप गलत बोलते हैं कि हम लोग मोडर्नाईजेशन के खिलाफ

[श्री चतुरानन मिश्र]

हैं। हम तो कहते हैं कि मोडर्नाईजेशन इस देश में तभी संभव है, जब साथ-साथ बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन किया जाय। अगर एक्सपेंशन नहीं होगा और मोडर्नाइजेशन में मजदूरों की छंटनी होगी तो ये मजदूर जाएंगे कहां? आपने 1,47,000 उद्योगों को बंद कर दिया, मजदूर कहां जाएंगे, आप हमें यह बता दें। अब 15,000 व्यक्ति रोजाना इस देश में बेरोजगार होते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक कारखाना कम से कम ऐसा खोलना चाहिए, जिसमें रोजाना 15,000 नए लोगों को हम रोजगार दे सकें बजाए इसके, आप मौजूदा कारखानों को बंद कर देते हैं तो कहां से आपको धन मिलेगा, कहां से आपको पैसा मिलेगा? इस समस्या का निदान जरूरी है और इस समस्या का निदान तभी होगा, जब तक एण्टायर थिंकिंग जो आपकी है अर्थ-नीति के बारे में, वित्त के बारे में, आधुनिकीकरण के बारे में उसमें मजदूरों को जगह नहीं देंगे, तब तक इसका निदान नहीं हो सकता है।

चूंकि समय कम है, इसलिए ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (डा बापू कालदाते): कम नहीं है, समय समाप्त हो गया है।

श्री चतुरानन मिश्र: समाप्त हो गया, अच्छी बात है।

तो मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिर एक बात को दोहराता हूं, कई माननीय सदस्यों ने आपसे कहा है कि टैक्स अगर लगाना था तो प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना था। आपको कोई मना तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप करते नहीं हैं। बहुत से सुझाव आए हैं, उनको आप देखिए। इस नीति के जरिए आप राज्य-सरकारों के बजट को अस्त-व्यस्त करेंगे। वे सब बातें आ चुकी हैं, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इस बाढ़ के चलते बिहार की जो भयंकर स्थिति हो गयी है और इस सूखे के चलते भयंकर स्थिति हो गयी है, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में कोई आश्वासन आप दें।

अंत में, जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर आप ऐसा करते हैं तब तो हम समझेंगे सार्थक काम के लिए पैसा दे रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल निरर्थक काम के लिए एक भी पैसा आपको न दिया जाए। यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill. At the outset, I would like to point out that as we are approaching the next financial year, we should go into the question of collecting more revenue without resorting to further taxation. That point is very essential and that should also be seen here.

First of all, I would like to elaborate on two or three points It is an admitted fact that there is a tremendous tax evasion now. If we could curb it even slightly, we would have collected this Rs. 250 crores that we are trying to collect today by passing this Bill. A few glaring examples of tax evasion are there I do not want to mention the names of all big houses of business hereon evasion of tax. We have not been able to touch upon them. There is the self-admitted evasion and criminal breach by Mr. Lalit Thapar. He said on his own, he had evaded tax of Rs. 14 crores. He paid only Rs. 1.1 or 1.2 crores, hardly ten per cent of it. This is just one example I am giving. There are several other houses.

The Minister had come here for Rs. 250 crores because we could not collect taxes effectively. So it is important that we are more concerned about tax collection. I would like to point out one thing here. Hon. Minister, Mr. Poojari, gave an assurance in this House. I was happy to read it; I was not present in the House then. About the industrial house, Reliance, he gave an assurance that whatever had been committed to here would be carried out. The same thing, I have to say, about Bombay Dyeing, about Thapar and about Orkay and other business houses. Some admissions have been made. Let the Minister state that he will be able to collect whatever is due from them before the next Budget Session. This is very important and I am seeking this assurance from the Minister. The amount is not very significant because tax evasion comes to the tune of

Rs. 20,000 crores. That is the estimate. If they collect at least Rs. 250 crores, that will show the determination of the administration to do something, that they mean what they say.

Coming to the next point, it is important that we raise this amount. All right. We should support this Bill. But, is all this money going to be spent effectively for the purpose it is meant for? A few days back, I read a report of the Comptroller and Auditor General of India where he has criticised several State Governments, both Congress and Opposition Governments. The administrations are generally the same. There is no big difference between them. The Comptroller and Auditor General said that Rs. 100 crores, actually it is Rs. 102 crores, remained unutilised. Rs. 85 crores were diverted and Rs. 100 crores were paid for past liabilities. Thus, Rs. 285 crores were not properly utilised. You give them money and when auditing is done, this is what is found out. Sir, this misutilisation, you may call it diversion, is growing. This is something horrible. Some time back—I do not want to name any State Government here—a correspondent of a renowned newspaper gave examples as to how the relief work money was misappropriated. At some places, we sometimes take voluntary agencies with us, Government give money for fodder at Rs. 3 1/2 per cattlehead. They say we have got 50,000 cattle. But if you actually count them, there would be only 5,000 What is to be done about it? Relief works are carried out by contractors. In Gujarat at least relief works are carried out by Government. But even there one Collector has said 15 per cent bogus persons are marked as present. We are employing 15 lakh workers per day. That means Rs 20 lakhs are misappropriated. For that I don't hold Ministers responsible. That is not the idea of my saying this. We are all responsible. Opposition parties are doing just the same thing as what is being done here Relief work is very important.

Another important thing is price rise. Price rise till this year has remained under one digit inflation. But by October end it went up to 9.4 per cent compared to last year and in November/December we might cross the double digit, although our industrial structure is no longer that much dependent on agriculture as it was before. Therefore, cement, fertilizer, steel, are not that badly affected. Then, electricity might be affected in March, April and May. With the substantial improvement in our industrial structure if the digit of inflation compared to last year is higher by 9.4 per cent, then this time perhaps we may make a record of crossing the double digit. We might go up to 14 per cent. That is the estimate.

Once inflation starts at this speed, then tax evasion is also there as a concomitant factor; then, corruption is also a concomitant factor. And then the Government would come with a greater deficit financing. They will just print more money. "What is wrong in it?", they say and they also qualify it saying unless production grows, it is dangerous. In 1950 Rs. 1,400 crores worth currency was in circulation. Today it is more than Rs. 28,000 crores. Production has not grown that high. And deficit financing that was estimated at Rs. 6,000 crores it is going to grow higher. Now, what will be the total effect of all these things? Then they will say taxation will be more. I am not against the taxing move. But this is like a diminishing return. Excise, when it was first imposed, was Rs. 30 crores collection through indirect taxation. Now it is Rs. 30,000 crores—there is 1000 time growth. In the year 1950 we collected from indirect taxes Rs. 225 crores; this year we are going to collect Rs. 30,000 crores; that is. 125 times more money we are going to collect. There is no commensurate growth of production and, therefore, price rise occurs. Who is going to give this much money? You are collecting this much money. If you are collecting this much money, then, naturally, evasion is bound to take place and the evasion also is this much, much more than what you are collecting. So, sometimes officers are happy over this and they say, "We have collected so much." I have said to them, "All right. You have collected so much But there may be complaints from people which might not have been entertained.

[Shri Chimanbhai Mehta]

When they make a profit of one rupee, the minimum that they give to the Government is seven or right rupees and, in one case, I counted and found that it was sixteen times more. Naturally, they may also think as to why they should not evade But the big industrial houses cannot always evade and sometimes it becomes very difficult for them because the Excise Inspectors and others are there. There are manipulations, of course. But this sort of taxation is hitting our own industries. I have given the example of the textile industry which has been ruined because of very high taxation. Now, industries are closing down, but smuggled goods are being sold in the market. If we remove the Excise Duty on the textiles, on this one item, then the smuggled cloth worth about three thousand crores of rupees would not come into the market.

So, Sir, to whom would they give relief? To the drought-affected people, to the newly unemployed people or to the sick industries whose number is growing every year? Every year ten thousand units more are added to the number of sick units which have been closed down Today, it is more than a lakh.

AN HON. MEMBER: It is 1,24,000.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Yes Therefore, the Government should really consider the fact that its taxation policy is not really effective. It may give you more revenue, but it leads to greater evasion. Therefore, one has to consider all these aspects and come to proper conclusion. We are worried about the problem of tax evasion. There is one more thing Public mortality is affected very badly by this. I do not say that what I am speaking is all my own I would like to quote the words of a very respected person, Shri B K. Nehru. Mr. B. K Nehru observes—this is a Government publication and this appears on page 297, on "Black Economy"—like this :

"Corruption is rampant in every sector of our society. A large number of politicians and Ministers are corrupt...."

You see, he is not talking of a small number, but he says "a large number of politicians and Ministers are corrupt". Then, he says :

"Corruption is universal in the lower ranks of public services. It has affected the middle ranks as well and is now affecting the apex of our administrative structure."

A few days back, I heard one of our leading Cabinet Ministers saying that even the Supreme Court has become the heaven for smugglers, tax-evaders, and so on. So, where is this leading us to? This is a heart-burning story. Therefore, Mr. Chaturanan Mishra was complaining: "Have you become so dumb that you are not able to speak about a Minister who is spending crores over a marriage function? From where he got all this money?". We are used to it. We are not tackling it. Mind you, I would like to tell you one thing. I do not want to taunt anyone, whether it is your or my party. What is happening in Andhra Pradesh, in Karnataka?

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: What has happened in your own House?

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: That is what I am saying. This is universal, Sir. Don't you think so? I have told that this is universal. Therefore, I am making my self criticism. Let us all start. I like Mr. Chaturnan Mishra's criticism. We should see that all Governments also behave, sometimes nicely. I do not say that Mr. Jyoti Basu can be termed as others. That is not the way. I am not clubing everyone. All of us not are in the same bracket. This is a universal problem. Therefore, let us come to some conclusion. (*Time bell rings*) This Bill is being passed, not because it is the ruling party's Bill but because it is for a very good cause, a worthy cause For that the money that is required should be given, without any condition. But there are other ways also of mobilising greater revenue. Let the

Minister ponder over it. Is he prepared to give an assurance that before the Budget session he will try and see that more money comes in? That will inspire others.

Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): The House stands adjourned for lunch, to meet again at 2.30.

The House then adjourned for lunch at thirty-six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock **The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai)** in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. S. P. Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री जसवन्त सिंह जी ने जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये और वित्त (संशोधन) विधेयक, 1987 का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मुझे इस बात पर आपत्ति है कि अध्यादेश के जरिये नये प्रकार के कर लोगों के ऊपर लगाये गये है और विशेषकर मैं यह बात इसलिये भी कहना चाहता हूं कि संसद् का पिछला सत्र 3 सितम्बर, 1987 तक चला था और इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों में यह बतलाया गया है कि इस देश में अभूतपूर्व सूखा पडा है उससे उत्पन्न जो संकट है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों को राहत देने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसीलिये 19 सितम्बर, 1987 को अध्यादेश जारी किया गया। मेरा निवेदन यह है कि इस देश में सूखा करीब करीब पिछले जुलाई या अगस्त के आरम्भ में शुरू हो गया था और इसलिये सूखा कोई ऐसी चीज नहीं थी कि सरकार को उन्हीं दिनों यह दिखाई पड़ा कि 18 और 19 सितम्बर, 1987 को ही अध्यादेश लाना पड़ा। मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष ने बार-बार अपनी यह व्यवस्था दी है कि जब तक आवश्यक न हो तब तक अध्यादेश के अधिकार का प्रयोग सरकार को नहीं करना चाहिये। मेरी राय में ऐसी आपतकालीन स्थिति नहीं थी। 3 सितम्बर, 1987 तक संसद का जो सत्र चला था उसी सत्र में विधेयक लाया जा सकता था। इस प्रकार का अध्यादेश लागू करके न केवल यह सरकार अलोकतांत्रिक काम कर रही है बल्कि संसद के जो अधिकार है उन पर भी कुठाराघात कर रही है। इसलिये मैं इसको अनुचित मानता हूं कि अध्यादेश जारी करके नये प्रकार के कर लगाये जायें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जैसा उद्देश्य और कारणों में बतलाया गया है जो 5 प्रतिशत अधिभार लगाया गया है उससे सरकार को आशा है कि 210 करोड़ से 240 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय होगी जिसको सूखा क्षेत्रों में राहत कार्यों में खर्च किया जायेगा। मेरा इस संबंध में यह कहना है कि बिना अतिरिक्त कर लगाये भी यह कार्य किया जा सकता था। बहुत से सरकार के फजूलखर्ची के ऐसे काम है जिनको रोका जा सकता था और उस रुपये को सूखा राहत कार्यों में लगाया जा सकता था। इस सिलसिले में मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं अभी कुछ दिन पहले समाचार पढ़ने को मिला कि राजस्थान में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी यह सर्वविदित है कि राजस्थान में अभूतपूर्व सूखा पड़ा हुआ है ऐसी स्थिति में यह बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान में जाकर केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक करने की क्या आवश्यकता है? इस सिलसिले में समाचार-पत्रों में यह भी पढ़ने को मिला कि वहां पर अनाप-शनाप लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं.. **(व्यवधान)**

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रि परिषद की बैठक सिद्धान्त रूप में जगह जगह होना उचित नहीं है। अगर हो भी तो उसमें जो खर्च हो वह बहुत कम होना चाहिये। अभी पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रधान मंत्री जी गये। प्रधान मंत्री जी ने एक नयी घोषणा की है कि इस देश में जो 439 जनपद हैं उनके जितने भी जिला अधिकारी हैं उनसे प्रधानमंत्री जी अलग अलग स्थानों पर जाकर के सीधे

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

बातचीत करेंगे और इसी प्रक्रिया में पिछले सप्ताह प्रधान मंत्री जी भोपाल गये थे और उन्होंने इस कार्यक्रम की प्रथम किस्त में 90 जिला अधिकारियों को संबोधित किया। मान्यवर मैं इसको अनुचित मानता हूं। इस कार्य में सरकार के चाहे 50 हजार खर्च हो या दो लाख खर्च हो लेकिन यह सर्वविदित है कि जिला अधिकारी जब आयेंगे जो उनके साथ अन्य लोग भी जाया करते है और जहां प्रधानमंत्री जी आयेंगे वहां भी दूसरे लोग जायेंगे तो इसमें लाखों रुपया खर्च होगा। इस प्रकार के बहुत से छोटे-छोटे उदाहरण है। जब कि हमारे यहां पर कार्यभार बंटा हुआ है और जिला अधिकारी अपनी राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं सबका काम बंटा हुआ है। तो क्या आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री जी 90 जिला अधिकारियों को भोपाल में बुलावे और उनसे बात करे। अगर कोई ऐसा जिला अधिकारी हो जो सरकार की नीतियों का पालन नही करता हो या उल्लंघन करता है तो उसके लिये राज्य सरकारे है और राज्य सरकारे अपना रिपोर्ट केन्द्र के पास भेजती हैं। मैं फिर उदाहरण देना चाहूंगा कोल इंडिया का क्योंकि इसमें आपको जो अतिरिक्त आय होगी वह मेरी समझ में नहीं आया मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि 210 से लेकर 240 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। 1985-86 और 1986-87 में बिहार में कोल इंडिया को 404 करोड 18 लाख का घाटा हुआ है और इसके आधे के बराबर हो आपको अतिरिक्त आय मिलेगी। इसी प्रकार स्कूटर्स इंडिया लखनऊ में केवल [illegible] का घाटा 1986-87 का 23 करोड़ 35 लाख है। इसी प्रकार से त्रिवेणी स्ट्रक्चरल इलाहाबाद [illegible] करोड 39 लाख 28 हजार है। इलाहाबाद में भारत पम्प [illegible] एक कुल घाटा 18 [illegible] हजार का है। यह घाटा इन चार पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्ज में कुल 453 करोड़ 43 लाख 63 हजार रुपये का है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फजूलखर्ची और यह जो पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्ज में घाटा होता है इसका कारण यह बताया गया है जिन उद्देश्यों से उद्योग खोले जाते हैं उनके अनुसार इन में काम नहीं होता है। इलाहाबाद में सरकार ने घाटे का कारण यह बताया है कि वहा पर पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई नहीं होती है या बिजली की कटौती होती रहती है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई करना या कटौती करना तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम है और केन्द्रीय सरकार का भी अपना एक इनर्जी मंत्रालय है तो सरकार का काम है बिजली की आपूर्ति करना या कटौती करना तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के जो मैं छोटे-मोटे उदाहरण दे रहा हूं अगर इन की ओर ध्यान लगाए तो इस तरीके से अतिरिक्त भार और वह भी अध्यादेश के रूप में सरकार को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं सरकार का ध्यान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 1985-86 की सप्लीमेंटरी रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इसके कुछ उद्धरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं जिसमें इसी बात की चर्चा है कि सूखे के सिलसिले और बाढ के सिलसिले में या जो दैवी विपदायें आई हैं उनके सिलसिले में केन्द्रीय सरकार जो रुपया खर्च करती है या राज्य सरकारें जो रुपया खर्च करती है उसका अपव्यय होता है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, सन 1985-86 की रिपोर्ट में इस तथ्य को बड़ी बेबाकी से कबूला गया है कि जो राहत का लाभ है वाकई उन लोगों तक तनिक भी नही पहुंचा है जो प्रभावित थे बेसहारा थे या जरूरतमंद थे। महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक ने इस तरफ अपनी चिन्ता जताई है कि प्रभावित लोगों तक सहायता राशि की झलक भी नहीं पहुंची क्योंकि अनेक राहत कार्य तो ठेकेदारों के सुपुर्द कर दिये गये हैं और प्रभावित लोग राहत की बाट जोहते रह गये। फिर आगे इसी [illegible] इस रिपोर्ट में इस बात [illegible] किया है कि राहत कार्यों की वास्तविक उपलब्धियों और वित्तीय प्रगति का सत्यापन न तो केन्द्रीय सरकार के स्तर पर किया गया और न राज्यों ने ही ऐसे किसी बावेला में पड़ने की जरूरत महसूस की। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की खास तौर पर चर्चा करते हुये कहा गया है कि वर्ष 1985-86 या पिछले वर्षों

के दौरान रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये आबंटित 12 करोड़ 99 लाख की समूची राशि उन कार्यों में बहा दी गई जिन में ठेकेदार मानवीय श्रम शक्ति के बजाय मशीनों का बेहिचक इस्तेमाल कर रहे थे।

मान्यवर, आपको यह विदित है कि सरकार की एक योजना है, फूड फार वर्क, काम के बदले अन्न। इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो ग्रामीण इलाकों में जहां पर विकास नहीं हुए हैं, सड़कें नहीं हैं, तालाब में पानी नहीं है या तालाब वहां पर खुदा हुआ नहीं है मवेशियों को पानी पिलाने के लिए तो वहां पर इस प्रकार की योजनाएं शुरू करती है और दूसरा इससे जो भूमिहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं वे अपना जीवन-यापन भी कर सकते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी हो सकता है। लेकिन, मान्यवर, इस रिपोर्ट में थोड़ा इस बात का उद्धरण दिया गया है कि जिस काम के लिए रुपया आबंटित किया गया है उस काम में रुपया खर्च ही नहीं किया गया बल्कि उस रुपये का दुरुपयोग किया गया। अपनी इस रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल ने यह कहा है, पैराग्राफ 1(1) :

The central Government extends help to the State Governments for providing relief assistance to a large section of the people affected by drought or flood. The relief measures include labour intensive works, provision of food and drinking water, gratuitous relief assistance to cultivators to mitigate their crop losses etc. etc. -:zHRa,

तो इस रिपोर्ट में सरकार की उस धन-राशि की चर्चा है जो कि केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्यों को दी जाती है या राज्य सरकारों द्वारा अपने सोर्सेज से एकत्रित की जाती है। जो प्रदेशों की कमेटी होती है पब्लिक एकाउट्स कमेटी उनकी रिपोर्ट के आधार पर कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट दी है। मैं ज्यादा उद्धरण न करते हुए केवल पृष्ठ 55 और पैराग्राफ 13.2 में कुछ राज्यों के बारे में जो चर्चा है उसको पढ़ना चाहता हूं। इसमें है :

In many States works wer eentrusted to contractors which meant that the real beneficiaries of the relief works were not necessarily the calamity stricken people.

यह उन्होंने कहा है कि जिनके लिए धनराशि जाती है उसका दुरुपयोग करते हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में जो फिजूल खर्ची है वह समाप्त होनी चाहिए। दूसरा, जो तस्कर लोग हैं उनको पकड़ा जाये, आर्थिक अपराधियों को पकड़ा जाये, गिरफ्तार किया जाये और सरकार की भी यह नीति है। जो कालाधन छिपा हुआ है चाहे अपने देश में या विदेश के बैंकों में उनको भी ला करके सरकारी कामकाज में लगाया जाये जिससे कि देश का विकास और उन्नति हो सके। इस संबंध में मै एक शर्मनाक घटना की चर्चा करना चाहता हूं जो कि "पंजाब केसरी" के सम्पादकीय में दी गयी है कि किस तरीके से सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके तस्करी के काम में लगे रहते हैं। 18 दिसम्बर का "पंजाब केसरी" है :

> "गत दिनों नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति के मानद यूनानी चिकित्सक हकीम मोहम्मद अबदुर्रज्जाक को 2.85 लाख रुपये के सोने के बिस्कुटों की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इन बिस्कुटों पर विदेशी मोहर लगी हुई थी। हकीम साहब यूनानी दवाओं की केंद्रीय अनुसंधान परिषद के निदेशक भी हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी भी है। भारत सरकार की ओर से, उन्हें पेरिस में यूनैस्को की एक बैठक में भाग लेने के लिए भेजा गया था। हकीम साहब को दुबई की एक उडान से दिल्ली पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तलाशी लेने पर 865 ग्राम वजन के सोने के बिस्कुट मिले जिन पर विदेशी मोहर थी। हकीम साहब उन्हें चोरी छिपे भारत ला रहे थे, पूछताछ जारी है।'

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

यह, मान्यवर, एक उद्धहरण है। मै निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का अरबों अरब रुपया, कालाधन लोगों की तिजोरी में बंद है। सरकार को इसको निकालने का काम करना चाहिए।

जसवंत सिह जी यहां बैठे है। पानी की चर्चा सब करते है। मान्यवर, राजस्थान मे, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड इलाके में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। वहां की नौजवान लड़किया हमारी मांएं, बहने, बूढ़ी-बूढ़ी महिलाएं 5–5, 6–6 किलोमीटर पैदल चलती है घड़ा लेकर चलती है, एक साथ 6–6, 7–7 घड़े लेकर चलती हैं, यह गाना गाते हुए चलती है :

"गगरी न फूटे खसम मर जाये"

वे विधवा होना पसंद करती है लेकिन पानी लाने की इतनी तकलीफ होती है कि गगरी फूट जायेगी तो पानी गिर जायेगा यह उनको डर रहता है। राजस्थान के हमारे माननीय सदस्य श्री धूलेश्वर मीणा जी ने राजस्थान का जिक्र किया। हम सब लोग जानते है कि राजस्थान रेगिस्तान है, पीड़ित है, पानी की समस्या है, अभूतपूर्व सूखा वहां पर पड़ा हुआ है। इन सारी समस्याओं की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि फिजूल खर्ची को रोका जाये, कालाधन जो तिजोरियों में बंद है उसको निकाला जाये तो फिर अतिरिक्त कराधान की जरूरत नही पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हुए जसवंत सिह जी के संकल्प का समर्थन करता हूं और इस विधेयक का मै विरोध करता हूं।

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I rise to support this very simple Bill which runs in not more than 2½ pages. It is a simple Bill and through it the Government proposes to raise additional funds for providing relief to the drought-affected farmers and the rural people. Though the additional collection that is proposed to be made through this proposed surcharge is only of the order of Rs. 240 crores whereas as far as I think not less than Rs. 1400 crores are to be spent in one year alone on this drought, still whatever can be raised additionally must be raised.

As my learned friends have already said, this year's drought is, no doubt, unprecedented; this is the worst drought of the century. In States like Rajasthan, drought conditions have been prevailing for quite some time for the last 3-4 years and I can say the situation is really very bad, and to help the affected people, we have to raise additional funds. Now, on the one hand, if we are to disburse additionally Rs. 1400 crores on drought relief works, how can our friends from the Opposition say that the deficit should remain at the same level? Deficit cannot remain the same if we do not raise additional funds, and if we can manage to raise additional funds, we will also be able to contain that deficit to a large extent. But both things cannot go simultaneously.

It is very good that countries like the U.S.A. and Japan have come out with assistance for providing relief to the drought-hit areas. But still we cannot depend solely on others' assistance. We have to be ourselves alive to the situation and help the affected people.

I congratulate the Government of Shri Rajiv Gandhi that despite such unprecedented drought, not a single man has been allowed to die of hunger or starvation. Our foodgrain stocks are there and we have been able to provide food for all. *(Interruptions)*. There is no report to say that anybody died because of drought 'Food for all' has been our slogan and we have been in a position to provide food to all in the country. We are self-sufficient in food. The whole world agrees to it.

Dr. Kalidate was, in the morning, talking about mobilisation of manpower. Mobilisation of manpower

means generation of employment. Our Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, has already assured the people of Rajasthan particularly, that one man from each family in the drought affected areas will be provided employment; it means that our Government is alive to the utilisation of manpower through providing employment to the needy, and about 25-30 lakh people will have to be provided employment. And if 30 lakh people are to be provided employment, you can imagine what will be the cost involved. The minimum cost will be around Rs. 135 crores additionally. But that is not the point. What is good about the surcharge to be levied is that it is going to be levied on people whose income is more than Rs. 50,000; it means that poorer sections are not going to be hit by this, and that is the beauty of this surcharge. Naturally, the rich people, the affluent ones, have to part with a slice of their cake to help their brethren, belonging to the weaker sections. From that point of view, I welcome this.

Now, our friends from West Bengal were criticising the Bill. But we all know—our Prime Minister has been repeatedly saying this—that whereas the Centre provides relief to all, the relief is not well-utilised. The money allocated is not spent on what it is meant for. As far as West Bengal is concerned, I know, the Central assistance provided for the flood-affected people was not disbursed indiscriminately. I mean to say that there was discrimination in disbursement. Those people who were affected but who had not voted for the CPI(M) were denied relief. This is the position in ninety per cent of the cases.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI (West Bengal): Question.

SHRI P N. SUKUL: You are talking about discrimination by the Centre.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: You certainly know the adage: 'You see your reflection in the world'.

SHRI P N. SUKUL: You are seeing your reflection in the Central Government. *(Interruptions)* My suggestion is that it should be ensured at all costs that the assistance which is provided by the Centre is well-utilised and it is utilised for the purposes, solely for the purpoes, for which it has been given. That is all.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Have you seen the CAG's Report on State relief.

SHRI P. N. SUKUL: I was amused to hear Mr. Jaswant Singh yesterday. He talked at length about the refurbishing of the Jumbo Jet for the Prime Minister during his Canada visit. He also criticised the Prime Minister and the Central Government for going to hold a Cabinet meeting at Sariska.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: In a sanctuary.

SHRI P. N. SUKUL: Why not? The whole country is ours. If my friends will excuse me, this kind of criticism reflects, as you say, your narrow and petty-minded approach. Drought or no drought, if our Prime Minister has to go any country, all precautions have to be taken for his security and for ensuring comforts for his entourage Drought or no drought, it is the responsibility of the nation. If you want that this should not be done, if you want that the Prime Minister must remain insecure even in a foreign land or that he should travel without proper security etc., certainly I differ from you I will again say that it is a petty-minded approach.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): There can be a difference of opinion as to what is proper and what is improper.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): How can you define?

SHRI P. N. SUKUL: As regards the holding of the Cabinet meeting at Sariska, I would like to point out that in my State U P., for a number of years when Mr. N. D Tiwari was the Chief Minister, Cabinet meetings

[Shri P. N. Sukul]

were held at district headquarters, at divisional headquarters and the people of the State welcomed it, greeted it and hailed it because that way the Ministers could come into contact with the people of different places and different regions and could understand their problems better.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The same thing is done in Maharashtra.

(*Interruptions*)

SHRI P. N. SUKUL: I was amazed to hear Mr. Jaswant Singh saying that about Rs. 47,000 is going to be spent on the Cabinet meeting at Sariska. On that ground, he says that it should not be held. This is no argument. A sum of Rs. 1400 crores is being spent on drought in a year and you are talking of an expenditure of Rs. 47,000! So, this kind of approach of our opposition parties must go. One thing is, of course, not clear from the Bill, how long this surcharge is going to continue. Naturally, since it is related to drought it is supposed to be there till the drought is there; whether it is in a big way or even in a corner drought is there, the surcharge will remain. But then I will request the Minister kindly to ensure that as soon as there is improvement in the situation, the surcharge should be dispensed with..

About farmers and other sectors people have already spoken. I will speak, especially for the salaried middle-class public servants, other low paid employees. It is said that no more than 10 per cent inflation will be allowed. This means, inflation is not going to be checked. If that is so, you must compensate adequately those at the lowest level or at lower levels. You can compensate the lowest level by providing them with relief or compensation by way of increase in D.A. or emoluments. To a bit higher sector you can help them by providing relief in tax. I have always said this. Last time also I said it and this year also I repeat the same thing. (*Time bell rings*). That is why in a summarised way I am saying that the limit for imposition of income-tax must be raised to Rs. 25,000.

The other thing is, lakhs and lakhs of the State Government employees are going on strike in February demanding wage increase and all that. I have read it in papers. Our Government at the Centre must be alive to the plight of the State Government employees. Also there are so many Governments which do not compensate their employees. In West Bengal I know that for a number of years a number of instalments of D.A. were denied to their employees. It was much later that they were allowed. Similarly in various other States also due justice is not rendered to employees. Then who will take care of them? The Central Government is the real Government of the country. All government employees must be cared for by the Central Government, maybe, through the State Governments. The Government at the Centre can alone give justice to these people. And towards doing justice to those people we must do two things which we have not so far done since independence. We must have a need-based minimum wage for all workers in the country Need-based minimum wage we have not been able to give to our workers so far. There must be a formula of giving need-based minimum wage. Also, since we are not able to check inflation or to stop it completely, there must be a national formula of dearness allowance acceptable and applicable to all the States and their employees, employees in the public sector, so that automatically they get increase; they do not have to suffer.

For the general people, not for the salaried class, I will say that if there is price rise, if there is inflation and our poor people, tribal people, other weaker sections, below-the-poverty people, if they cannot get two square meals a day, then it is a matter of shame for all of us.

So if our Government cannot
3.00 P.M contain prices, then it must come up with proper subsidies to feed the weakest-most people financially. The essential commodities must be subsidised. It must be the responsibility of the Government to provide food at subsidised rates, as in Andhra, as in Kashmir. In Andhra Pradesh, rice is two rupees a kilo. The same thing

can be done in the whole of the country. That will go a long way to satisfy our people.

I am sure our benevolent Government will give due consideration to these suggestions and do something positive through the next budget to provide relief to these sections. With these words, I support the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri Nirmal Chatterjee. Please take not more than ten minutes.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: I have a meeting at 3 o'clock. I am already delayed.

Mr Vice-Chairman, Sir, when hon. Member, Mr. Jagesh Desai, was referring to me, I was glad that some of us did want that there should be more collection from direct taxes, in order to meet not only the problems of the drought, but also.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M JACOB). The first round is not yet over. ..

SHRI NIRMAL CHATTERJEE. I have a meeting at 3 o'clock. You kindly be generous to me.

So, excuse me for saying so, I am not happy when I say the following words. It does seem to me to be another fraud. That is why I am intensely in agreement with the Resolution moved by hon. Shri Jaswant Singh. Why it seems to me so, let me explain.

Now the first thing to see is that the main part of the total collection of income-tax is derived primarily from people who are having a taxable income of less than Rs. 50,000. Now we can imagine, Mr. Gadhvi is not there he has quoted the figure of Rs. 240 crores. You will understand that his calculation is this. Four thousand crore comes from corporation tax, roughly Rs. 2000 crore from income-tax other than corporation tax. He feels that from out of this 4000 crore, he will collect 200 crore and he will collect 40 crore from income-tax. Now everybody knows that the corporation tax's ollection is primarily from public sector enterprises. Mr. Gadhvi is not here; I do not know who is taking notes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Jacob is taking notes.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: More than 50 per cent of corporation tax comes from the public sector enterprises. Which means what? Which means that more than 100 crore will come from the public sector enterprises. Which would mean that you have to compensate the public sector enterprises for that amount from your budget, or they will go into red of a brighter hue. So that means, your effective collection is no more than just 100 crores of rupees. I can give you this figure. Are you aware who pays what? There are 269 individuals who pay income-tax whose assessable income is Rs. 5 lakh in this land of Birlas and Tatas! And the number of those who are assessed to an income of more than Rs. 1 lakh is 5,359, according to the CAG's report. I have nothing to do with these figures. So, you can imagine what would be the collection from income tax. If the estimate is correct, that you are collecting around Rs. 100 crores, I call this a fraud for the other reason. The other reason is, you have all forgotten that a few days ago we passed a supplementary grant. You have forgotten one item, that Rs. 100 crores additionally, are being paid as CCS Cash Compensatory Support, to your exporters.

SHRI B. K. GADHVI: What is it.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: You were away. Should I repeat?

THE VICE-CHAIRMAN: SHRI JAGESH DESAI): No. He has taken notes.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: So, whatever you are collecting through the surcharge is eaten up by payment to companies as Cash Compensatory Support. You are getting a zero sum for drought.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is not correct.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Yes. I question anyone to controvert this figure. More than half the amount is from public sector. Out of the Rs. 240 crores if you eliminate nearly Rs. 130 crores, what remains is Rs. 110 crores. And Rs. 100 crores you are paying as CCS according to your supplementary budget.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is from the total.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: That is true. But the additional expenditure is Rs. 100 crores for CCS. So, the residual is Rs. 10 crores, for which you had to rush with the Ordinance. You don't think it is preposterous, you don't think it is a fraud, you don't think it is an eyewash. What else is this? This is my first objection.

Secondly, it has been pointed out that your collections are *via* a surcharge. This is another aspect of the fraud. You are denying the States. What we wanted is to raise the rates of tax so that the States get a higher share. Nothing from this residual Rs. 10 crores will go to the States, not even in the name of drought. I quoted the figure. You were not present. I want you to answer. I will come back and listen to you.

SHRI B. K. GADHVI: Kindly repeat. ... (*Interruptions*).... ..

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: My fact is, I said, out of the Rs. 240 crores, the corporation taxes are primarily from the public sector enterprises. Do you disagree? You don't. I say, Rs. 130 crores will come from the public sector enterprises and therefore, they will go red unless you compensate. So, that is fixed there. The residual Rs. 100 crores, I say, you pay towards CCS. You are left with Rs. 10 crores only. I want your officials to check the arithmetic and answer me. Now this is one aspect.

Sir, the problem really is, there is a crisis of resources. Let us face the fact. The deficit will certainly increase. To what extent, I want to get an answer from you. But you refuse, firstly because you are not sure and, secondly, because you do not want to state a higher figure. Otherwise, you could at least give us, what is known as, guesstimate. You refuse to give us a guesstimate also because, I say, it is a hoax that you are perpetrating on the country, and your crisis of resources is such that if you say that you will raise the rates of taxes, you want to trust the same people whom you were criticizing yesterday. I mention Wadias. You trust not only Reliance but also Wadia whom you discovered, to your advantage, to be such a person who has tried to influence your department. Therefore, if you raise the taxes, you say, they will not comply with that. More black income will be generated. So you are in a fix. Your trust requires that you reduce the direct taxes so that they can voluntarily comply. That is one aspect of your resource crisis.

The second aspect of your resource crisis as so many have pointed out, is, despite the very optimistic estimate of the Planning Commission you have crossed the deficit financing range. You consider that to be manageable. The Planning Commission had a different view of what figure would be manageable. They have produced a figure of Rs. 14,000 crores.

You are going to double that amount in the course of the Seventh Five-Year Plan This is the second aspect of your resource crisis. You contest that.

SHRI B K GADHVI: That will be known only when we come with the final balance sheet, not now.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Already you have crossed Rs. 14,000 crores; already you have reached Rs. 18,000 crores. Where will you reach in another two years? It will require a much better quality of bluff to convince the people that you would limit it to Rs. 18,000 crores. So, your source of resources, your resource of resources is going to the market for borrowing. You are already faced with an internal debt trap. Already you are having an internal debt of Rs. 800/- crores. I do not know whether you are certain that you will not be there to preside over the Government in the years to come and that, therefore, you are not responsible for the future of the country. This internal debt along with the external debt will be there. You have also been told to see the example of Brazil and others. The World Bank advised us. After a very interesting growth in motor car industries and electronics and other sophisticated areas, all those countries have got into debt traps. You are once again entering into that. So, for any kind of resource mobilisation the road is blocked. The excise duty, the increase in the administered prices, you know, people have started opposing. That road is also closed. This is the crisis that you have invited not only on your head but on the head of the country also. (*Time bell rings*) I am concluding. I have so many other things. I do not know when I will get an opportunity to speak. I have also got a meeting.

But the problem is Why this resource crisis? The resources of a country are reflected in the ownership of assets and the structure of production. All this resource crisis that you are facing is not faced by Birlas. Drought or no drought, in the course of three years their assets grow from Rs. 2,000 crores to Rs. 4,000 crores. Are they facing a resource crisis? In three years they double their assets. It depends on the nature of ownership. This is true for all such large houses. Birlas now head it, Tatas are close behind and all others, including Wadias and the Reliance Group. So, this is the structure of ownership which takes away what resources are there. These large houses together have larger assets than your public sector. Don't forget this. Therefore, you have brought this to such a pass that we will be vindicated when we say in our party programme that for the Indian economy there is no other alternative but to break this pattern of ownership of assets, to take away the assets of these large companies. If you cannot do that, you have no solution to the problem of the economy. Only then will be generated a demand which will require a structure of production which is not dependent on motor cars or TV sets. What a dangerous ground you are approaching, you do not know. There was a pent-up demand for cars, thanks to Birlas. That pent-up demand is reaching its limit through the production of the Maruti cars. Tomorrow, next year or the year after that road of advance is going to be closed. That is going to be the same for other sophisticated units of production also. Why this is bound to happen is because it was a pent up demand reaching its end. Every economist will tell you about this. You also claim that you understand economics. Are you aware that in the agriculture sector, where 70 per cent of the population lives, the per-capita income over the last forty years has not grown? If that be so, why do you get your demands generated? Then who should produce more foodgrains, more pulses, more oilseeds? They are all required only for a narrow size of your population You have created a crisis on the demand side also because of this.

[Shri Nirmal Chatterjee]

On the supply side, everybody knows, I will not take your time, you have tagged it to the foreign technology. as if it is that which can solve your problem. You have imported fertilisers. Fertiliser is a foreign technology. Yet the yield from fertilisers is the least in our country compared to the users of fertilisers of other countries Your economy is this much inefficient because your economy prospers in terms of the profits of the Birlas, not in terms of output which is consumed by the people. It is in this context that I say your bringing in of the Ordinance was a hoax to cover up your total worthlessness before the situation which you can no longer handle. It has gone out of your grip. Only on one point I differ. He thinks it is roguishness to introduce the ordinance, but I do not know whether it is a madness which, it is said, God confers on some people .. *(Interruptions)*

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh) Sir, ours is a mixed economy.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE Is it mixed economy or mixed up economy?

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH. Our capital market is arousing interest throughout the world, including China. Three experts of our country have been invited there. It is a matter of great satisfaction and significance that even the Chinese are keen to study our capital market. It is a big question which Shri. Nirmal Chatterjee should have taken note of. But since he is running away, I would say only this much that along with that the legislation has to be welcomed, because without disturbing the general trend of our tax structure policy, surcharge is imposed on a slab of income which is Rs 50,000 upward and Rs. 1 lakh upward If that be the situation of an economy, to meet the exigencies created on account of drought and floods such a surcharge is a very welcome step.

One modification I would like to make to the proposal that Shri L. K. Jha put forward yesterday that the bank credit facility should be made available for giving incentive to production There I want to make a little distinction between the two classes of people for whom the bank credit facilities are being provided. There is a poorer section of society which is contributing at the present juncture the most of our national economy. There is a richer section of the society whom we are going to tax through this surcharge. I am very frank that they have not contributed appropriately to our national economy. So I agree with that part of the reservations that bank credit facilities should be made available for that section of the society which is really below the poverty line, giving incentives to production for a small scale sector and middle scale sector. But I do not think it is necessary to provide credit facility if a particular sector is not responsive to our national economy because at this juncture we are facing constraint of resources.

Now, there is one more remark made by Mr. Nirmal Chatterjee that technology revolution or technology import in all aspects is not there Import of technology has to be welcomed because we want to keep pace with the world development and should not lag behind. But in this import, we have to keep in mind the balance of trade, that is, export and import. The accepted principle of technical knowhow has to undergo the process of indigenisation with suitable amendments and improvements. The selection should be what we need and what others are prepared to give.. This transfer must be followed up by counter-trade agreement and buy back arrangements, then, it would be safer.

Now on one thing that I have not been able to follow in clause 3 of the Bill. Certain exemption has been made for NRIs and no surcharge is payable by them Why an exemption has been made for NRIs? By and large NRI investment has been welcomed and in spite of the fact that this money went as a process of capital flight which must be checked by internal market.

After it has been brought back NRIs must not be allowed to invade our national capital market. They have not responded well to our schemes and went on bargaining at the cost of national capitalism. Therefore, investment must be restricted to the creation of new industries and they may be permitted to come with new technology from outside for the establishment of a new industry but must not be allowed to scarp the existing industries. If that is the principle, I do not know why the hon Minister has provided them an exemption for the ayment of surcharge because that will be distinguished with national capitalism and NRIs who want to come back to India for the purpose of investment.

Now the health of our economy has been commented upon It is true that we are facing the problem of cost overruns in this country. The question of savings is also involved in this Bill. To avoid cost overruns would be a long-term policy but it has to be taken note of because the projects which were costing at one time Rs. 50 crores have now become Rs. 500 crores We do not know, it may reach to Rs. 1000 crores. That is one aspect

So far as the time overrun is concerned, it is a phenomenon which everybody knows and the HBJ pipeline is ready in time but the projects for which it was meant are running behind schedule. There has been a lot of debate on this and now we shall be suffering, loss on interest and capital. Now that has to be taken care of. Otherwise, no surcharge will be solving our problem beyond a certain limited capacity.

Now the final point is regarding curtailment of the wasteful expenditure. I am not referring to external debts but certain analysis of internal debts. That would be my last point. If we really do not cut the wasteful expenditure then our capital market would be failing in many respects Had there been a long debate, I would have stated those points regarding debt servicing and repayment of the principal and interest charges. Now over the years the Government has to borrow more to repay loans and interests. Now there is one phenomenon which is being introduced in our economy. Apart from Government taking loans/debts, there are various corporations of the Government which have started taking loans. For instance, Mahanagar Telephone Nigam, NTPC etc. They are floating their own bonds and it is likely to lead to economic chaos Apart from the Government if corporations also take loans without thinking that they have to pay back the principal as well as the interest, it would lead to economic crisis Even after partition, the interest on the Government paper was 2 1/2 to 3 per cent. Now it is 12 per cent or even 15 per cent. This points out that our net borrowings are increasing from year to year and we are unable to service our debts out of service of current income They are not being out of service, that is current income minus current exepnditure. Now it is being serviced or paid out of further borrowings. That is what I wanted to point out that this is now being paid out of further borrowings Even our great grandchildren would have to suffer on account of our present day policy of expenditure The private sector has to pay out of their own service. Therefore, they have to be efficient They cannot afford to be negligent. Otherwise they will go bankrupt. In highly industrialised countries like Japan and Germany, the inflation rate is hardly 1 per cent. The higher inflation is indicative of bad management because even if it is admitted as 8 per cent in comparison to others. It has to be taken caution of. The present economic measures in the administration should be continued to be in force and not allowed to become stale after two-three months of initial zeal. As we are borrowing in short term market to create long term assets, therefore, the use of assets

[Shri Bir Bhadra Pratap Singh]

should be careful and those investments should give genuine profits. We must keep a close watch on the world economic situation because 70 per cent of our foreign reserves is in terms of dollars and only 30 per cent is our rupee reserve and we are still trading with much more dangerous zone, that is EEC countries whose money has become more stable Therefore the only answer today is a drastic cut in the wasteful expenditure. I think the hon. Minister will think about it seriously and will give a suitable reply. Now since the surcharge is levied against haves, therefore, I support it. Thank you.

SHRI V NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman Sir, the Finance (Amendment) Bill, 1987 has been introduced by the hon. Minister to impose a five per cent surcharge on income-tax We know fully well that our country is reeling under a severe, unprecedented drought. There are also floods in two States, Assam and West Bengal. In the South, in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh, we did not have sufficient rains even-though there had been a monsoon period The drought situation is acute in Bihar and Rajasthan. We did have a planned economy. Our expenditure on various heads both plan and non-plan, is limited. Yet, we could not cope with the existing situation and therefore, this remedy is sought. Sir, I saw a newspaper report about a week back about a report of the Auditor General The Auditor General has submitted a report that the State Governments, whether they are Congress-I ruled States or Opposition ruled States, have diverted funds which have been provided by the Central Government for the 20-Point Programme or for developmental programmes, for other purposes. The amounts which have been given by the Central Government are only for purposes of developmental activities in rural areas and urban areas. The State Governments which get the funds from the Centre have to business to divert the funds from one head to another. When they submit a scheme to the Central Government for sanction of funds they specify a particular purpose But the amounts are not utilised for the purpose for which the amounts are given by the Central Government Central teams visit the areas concerned and submit reports After satisfying itself about the requirements, the Central Government gives the money. But the State Governments are utilising the funds for their populistic measures, just to appease the people by a timely, but temporary, remedy and not for long-term remedies This is an important point which the hon Finance Minister has to check up.

Secondly, Sir, a lot of people from the other side say that there is no development in the country. But the position will be clear if we go through the statistics for the past three years. In the agricultural sector, last year the production was 157 million tonnes of foodgrains. This year, it is expected to be 135 to 140 million tonnes. In spite of the severe drought conditions prevailing in some States, we are able to maintain it because of our planned development in irrigation. We got irrigated an area of 62 million hectares which was, in 1965, only 21 million hectares. In sugarcane production, now our target in 1986-87 is 175 million tonnes. We are maintaining the statistics of last year. In cotton production, we are just above the target of last year, five million bales. Originally, it was 100 lakh bales Last year it was 95 lakh bales. In sugar production, we are reaching the target of last year, namely, 84.36 lakh tonnes, this year also. In oilseed production, we have lagged behind because of the acute drought condition. We are deficient by 12 lakh tonnes in this year. But we will be able to manage the situation because of rapeseed and mustard whose production has gone up. In the industrial sector

also, in 1986-87 we have achieved the target of a seven per cent increase. Therefore, in the planned economy we are pumping already so much money in the public sector, the Government is especially looking after the development of the agricultural sector and the industrial sector simultaneously, and, therefore, we are able to manage the drought situation this year. In 1965 we had seen several starvation deaths, but this year not even a single starvation death has taken place in spite of the acute drought conditions prevailing in two big States like Gujarat and Rajasthan for the past four years. The State Governments have done a tremendous work in organising cattle camps, in providing drinking water and fodder for cattle The Central Government is providing assistance to the State Governments concerned. Therefore the Central Government should be given a commendation for the services rendered by it, for realising the seriousness of the situation and helping the States concerned. I would like to say in my State, Pondicherry, last year and this year we had insufficient rains, we have not had sufficient rains, and we asked the Central Government for an assistance of Rs. 5 crores from the Central Pool. We required the assistance for the purpose of fodder, water supply schemes, for providing subsidy to the agriculturists etc. But we could get only Rs. 69 lakhs from the Central Government. This is what I want to bring to the notice of the honourable Minister.

Another important matter I wish to place before the House is this. This concerns both the ruling party as also the Opposition Presently two notifications have been placed before the House by the honourable Minister relating to tax on textile goods The first notification was issued in November 1987 and the second notification was submitted by the honourable Minister on 9th December, 1987. In the Budget on textile goods the Government fixed the *ad valorem* duty taking a metre as a unit, that is, taking the price of the cloth per metre. As per the original Budget proposal on one metre cloth costing between Rs 22 and Rs. 25 90 paise was the *ad valorem* duty. The *ad valorem* duty was Rs. 1.37 p. on a cloth costing Rs 37 per metre. It was Rs 60 per metre for a cloth costing Rs. 250 to Rs. 300 per metre. Now this has been replaced by these two notifications and according to the revised scheme the value of the cloth is no longer computed on a per metre basis. Now they consider it on the basis of 100 cms and 125 cms. When they do it, on a cloth costing Rs. 60 the person has to pay at the rate of Rs. 60 and on a cloth costing Rs. 600 also the big industrialist has to pay only at the rate of Rs. 60. This amounts to crushing the small weavers, the powerloom-owners and helping the big industrialists; the people doing business on a small scale are crushed, are suppressed. Another important and surprising thing is in the earlier dispensation if there was more polyester, the tax was more but now in this new policy if the polyester quality is 75 per cent more, the tax is less and if the polyester quality is 75 per cent less, the tax is more I would like a clarification on this from the honourable Minister. In the new textile policy which has been announced Government said they wanted to help people who are owning small industries, who are dealing in handloom industry. But the actual result of it is that the big industrial houses will get the benefit under the new scheme. And, Sir, the persons who are holding two or three small weaving machines will be suffering. I would like to know from the honourable Minister what the justification for this is. A variety of cloth costing Rs. 600/- is having the same tax as a variety of cloth costing just Rs. 60/- only! What is the rationale behind this system of taxation? I would like to know this. This is a matter of great concern for more than five lakhs of people in Maharashtra alone and in Tamil Nadu, there are more than two lakhs of

[Shri V. Narayanasamy]

people and in Andhra Pradesh there are more than seven lakhs of people You see, a person who owns power loom industry gets the same income as the worker If he gets two rupees, one rupee goes to the worker The worker gets the same income as the owner' Or, the owner gets only as much as the worker gets. Therefore, he is very much affected. I would like to know from the honourable Minister whether he is going to adopt the same policy which was announced by the honourable Prime Minister when he was the Finance Minister or whether he is going to stick to his present policy which will definitely cause injustice to the people in the lower strata of society. Sir, the new textile policy will not work and you would not be able to achieve the targets fixed in the new textile policy if you are going to continue with your policy. You see, in Punjab, they are going to close down the powerloom mills. It seems that they are going to go on an indefinite strike on this issue Let the honourable Minister kindly convince me on this issue and let him say that price is the consideration or criterion for the purpose of fixing the tax. Thank you, Sir

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) Now Mr Jaswant Singh.

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is customary at this stage for the Mover of the Resolution to thank the Members who have participated in the discussion which customary duty I would indeed perform now.

Sir, I cannot say that I am enlightened by all the interventions. We have covered a wide field. We started by referring to the levy of five per cent as surcharge on taxation ostensibly for the purpose of meeting the drought and we have gone wide afield, some of the Members having somewhat excitedly talked about the problems of, powerlooms, the various other aspects of industry as also about the fiscal situation in the country. These matters also have been covered. But the point correctly and significantly made by my eminent colleague, Shri Nirmal Chatterjee, was that normally the Finance Bill is a consequence of and has a closer relation with the presentation of the Budget which provides us an opportunity to examine the state of the economy to consider the fiscal policies of the Government and, thereafter, deliberate upon the Finance Bill as such However, none of the speakers had really touched upon this aspect Very briefly, Sir, I would like to consider just three broad outstanding aspects of what the state of public finance of the country is. Here we have to be really outside of the realm of nay-dreaming or of conjectures and to enter the arid empirical world of economic statistics, of whatever variety they may be. To my mind there are three features of the state of public finance in the country which are noteworthy.

First,—I think this is something which the honourable Minister has to reflect upon—there has been a noticeable decline in the rate of growth of total tax revenue, from 21.3 per cent in 1985-86 to 14.9 per cent in 1986-87 and a projected 7.2 per cent for 1987-88. What is alarming is—that is where the relevance of this particular ponit lies—that the sharpest decline has been in the rate of growth of receipts from income-tax which was 22 per cent in the year 1985-86, 6.2 per cent in 1986-87 and 2.9 per cent in 1987-88 Similar is the fate of the corporate taxes.

The second noteworthy feature of the state of public finance is that deficit financing has been continuously increasing from roughly Rs. 4 900 crores in 1985-86 to Rs. 8,285 crores in 1986-87. And it is an estimate, not even revised, of roughly Rs 6000 crores. And that is again where the relevance of the present measure lies. And, very briefly put, there is

a massive increase in non-Plan expenditure which has continuously been increasing from roughly Rs. 25,000 crores in 1984-85 to Rs. 27,000 crores in 1985-86 and Rs. 31,581 crores in 1986-87 and Rs. 34,116 crores in 1987-88 It is in these three lights that the present measure has to be seen. And I leave it for the hon Minister of State in the Ministry of Finance, to whom I apologize in advance because I have unfortunately to leave very soon; I am considerably delayed on account of an engagement. I am hitting the Government and running away I am certainly making my point. And I am open to the Government hitting me whenever they choose or whenever the next opportunity arises. I beg his pardon about going.

I will deal with just one or two aspects. One is about the price rise, because this is very close to all of us. But before I take up this question of price rise, during his intervention the honourable Shri Sukul, referred to this that I had said that the Prime Minister's picnic excursions—some hon. Members had referred to it as picnic excursions at Sariska and some hon. Members referred to it is the travels of Alibaba and his forty companions to Sariska—would cost Rs. 47,000. This is not the figure that I have given. The Prime Minister is insulting our intelligence by suggesting that the entire Cabinet visit to Sariska and staying there for two days is going to cost only that sum of money. According to my estimate—and the hon. Minister should enlighten us on this subject—it is going to be not less than Rs. 5 crores. The State of Rajasthan and the Union Government are going to share between them an expenditure of not less than Rs. 5 crores for this picnic of the Cabinet in Sariska to deliberate on the state of the nation It is much better for them to go to Rajiv Gandhi's farm, next door, to mehrauli

Hon. L K. Jha, that renowned economist, with whom I cross economic swords, so to speak, only with the greatest trepidations, made a point. He made four significant points I won't cover all the four. But he referred to price rise. And he said that we should really not be alarmed, that it is somewhat a reassuring situation and on a point-to-point basis the price rise is 8 per cent. And also referred to his having witnessed a down in the wholesale price index Sir, the price rise affects different people differently. I am sure an eminent personality like Shri L K. Jha is insulated from the travails of the ordinary. But I would like to bring to his notice that the Union Labour Ministry only on last Wednesday has given us to understand that the consumer price index for industrial workers will increase by 9.3 per cent. If you take examples like onions, they were selling in 1985 at Rs. 335 a quintal and now they are selling at Rs. 1021 a quintal And onions are day to day used. This reflected a rise by 204 per cent. I have got a list. But I do not want to labour the point The essence of it is that the price rise is not what an eminent economist like Shri L K Jha has said.

There are two other factors which I would like the hon. Minister to consider. One is possibly the sort of containment of price rise. I do think that here as against the run-away inflation what we are witnessing is on account of uncomfortable pressure of prices I put it to you. Sir, that on account of the drought, rough estimates inform us, possibly about Rs. 10,000 crores worth of purchasing power has been taken away from the rural sector.

Now, if the drought is spread all over the country in the fashion in which it is and Rs. 10,000 crores are lifted out of the economy because the farming community and the rural sector have not got that money in their pocket, it is going to do something to our economy. What that something is for the hon Minister and his Finance Ministry to determine I for one am not much assured that everything is as rosy as the Treasury Benches would have us believe I would also like to ask the hon. Minister whether it would be correct to say that another reason for the somewhat manageable price rise rate is a continuing increase in foreign trade deficit The second reason is the lack of purchasing power to which I had just referred. Thirdly, there is growing effectiveness of unaccounted money is in

[Shri Jaswant Singh]

circulation because the unaccounted money which is in circulation along with depression in the purchasing power .

हमारे यहा एक कहावत है अध्यक्ष जी कि और सबको काल पड जाता है गाव के बनियो को कभी काल नही पड़ता । तो उस हिसाब से मत्री महोदय इस पर विचार करेंगे जब अनएकाउन्टेड मनी सर्कुलेट कर रही है तो उसका असर भी प्राइसेस पर पड़ रहा है ।

Finally—anl it is a significant factor—is stagnation of domestic savings because there is a flight of capital abroad. Sir, I do not want to elaborate the point too much. We had a prolonged session last night. It was a kind of monolithic session last night which lasted till early this morning. I believe that the end-of-the feeling has invaded the House and I would be failing in my function if I said that because of this end-of-the-term feeling I withdraw my Resolution. That I cannot do because I am convinced that the Government has not come forward in the right measure to meet a terrible and grave wrong which has afflicted the country.

SHRI B. K. GADHVI: Sir, all old twenty hon. Members have participated in this debate and they have traversed a very wider area of economy that what is covered under the present small Bill. Therefore, Sir, before I try to meet their arguments with regard to the overall shape, strength and performance of the economy, presently I would only dwell upon the salient features of the Bill and the points that have been raised with regard to this Bill

Sir, Mr Jaswant Singh, Dr. Bapu Kaldate and some other hon. Members raised a basic point about the propriety of promulgating the ordinance Normally, as far as possible, in a democracy, enactment by way of ordinance should not be resorted to and that too particularly in the area of enactment which has got fiscal bearing. But they would appreciate that there were two reasons broadly and mainly It is not a fact that the Government was not aware of the drought situation in the country. The Government did know. But you also must be knowing that by August-September we get a total picture because of the erratic behaviour of the rains.

If there is no good rain in the early months of June and July still, however, if there are rains in the later part of August or something, then also some of the crops could be grown So, to understand the problem whether the rains are sufficient, whether the rains are adequate for the agricultural puposes, it is not merely the quantum of the rain which is the parameter for judging it but the time as to when it rains or when it does not rain is also important. By September it was crystal clear that there was a severest drought of the century. Then a package of measures was to be initiated and undertaken for the purpose of mopping up the resources to meet the drought expenditure. And this is one of the measures out of the whole package. This is not the only measure that we are taking. But we thought that it is better to promulgate it by an Ordinance because, by and large, most of the people who will have to pay the surcharge under this were to pay their advance taxes. And if we put the burden of putting the total surcharge, the laggregate surcharge arrears at a time, perhaps it would have been difficult and it would create a difficulty for them and, therefore, the promulgation of the Ordinance was made

SHRI KALPNATH RAI: Very good.

SHRI B. K. GADHVI And I don't think that there was any other intention But So far as the income-tas is concerned, the surcharge should also be facilitated to pay it by way of instalments. And the total picture emerged. Therefore, we thought that there is no other go but to mop up the resources of a particular time.

The second point which has been made on this Bill is: Why surcharge and not income-tax because the States are deprived? So far as the income-tax is concerned, States are not at all deprived This is not an income-tax. This is a surcharge on income-tax. But in my opening remarks I have said that this is imposed for the

very purpose of meeting the drought expenditure, and the intensity of drought varies from State to State. The help to be rendered to the States also varies from State to State. Just, for example, Rajasthan and Gujarat are there which are very hard hit States. There are other drought conditions in other States. But, for the purpose of illustration I am taking these two States If there had been income-tax instead of surcharge naturally as per the formula under the Finance Commission it would go equitably to all the States depending upon the population and all other factors and parameters. So, it would not be an action to raise the resources specially for meeting the drought situation and going to the succour of those people who are badly affected by the drought situation in their respective areas and respective States And that is why surcharged is imposed.

Sir, one point raised is for how long this surcharge is going to be. For the present, it is only for 1987-88, God forbid, there is no drought next year. So it is a very temporary measure. One point has been raised as to why the NRI has been exempted. Now this is only a one year measure With regard to the NRI investments and other things we have got various treaties with various countries and all other things So, if we were to collect this surcharge from them also then necessary changes in the treaties and agreements and other things were required to be done. Government did not think it fit that for a one-year measure all this should be done, and at the same time the revenue which we would have collected from the NRI incomes if we had imposed the surcharge on them would have been very nominal.

4.00 P.M.

So, from these two aspects exemption is given to the NRIs. Therefore, Sir, for meeting the drought situation including the expenditure we are incurring on our regular programmes of NREP, RLEGP and drought, it may be around Rs. 1800 crores or so. Apart from the NREP, RLEGP, the expenditure would come to the tune of about Rs 1200 to Rs. 1400 crores If the situation worsens it may go perhaps a little higher also. Therefore, Sir, as the hon. Members have pointed out when we have to meet the drought situation then inflation has also got to be contained. Otherwise although on the one hand we will be providing them with relief, on the other hand, if the inflation goes up and prices rise, then it will be hurting and accentuating bad conditions to the poorer sections of the society. And hence these additional resources by way of this surcharge and some railway fare increase. We are getting some help also from abroad and that is why all these economy measures, curtailment of expenditure, and a package of measure have been undertaken, and I may tell you that they are working well.

One point was raised regarding foreign assistance or what we are getting by way of foreign assistance from the World Bank, America, Japan and all other countries. As a matter of fact, India has not gone to any country with a begging bowl. They themselves have voluntarily offered the help and we have accepted it. So far as the World Bank assistance is concerned it is mainly for the purpose of meeting the balance of payments and all other grants and assistance from other countries. By and large, they are in the form of commodity grants only. You know that because of the drought there is a shortage of edible oils in the country, just for example I would say that in Gujarat, which is the highest producer of groundnut in the country not a single seed has grown in the Saurashtra region Very bad situation. And so is the case in other States also With regard to pulses, Rajasthan used to provide good pulses Other States also used to provide good pulses. Even in good years there is shortage of pulses in this country and so we have to import something. We have to provide it. And, therefore, the question of balance of payments was there and the World Bank assistance is by and large mainly to meet the bop problem.

Sir, Shri Nirmal Chatterjee, since he has now returned back

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: I have only come back and not returned back.

SHRI B K. GADHVI: He has touched on very many areas of borrowing, inflation, and other things. I do not deny that

(Shri B. K. Gadhvi)

there is a pressure on the economy not only because of the drought situation. And we are aware that this is not the only factor which is putting pressure on the economy, but that there are various other factors, national and international, which are responsible for it. Our expenditure in certain areas is there and to meet certain obligations we have to spend something. Internationally also as our external trade linkage as is concerned, our exchange rate linkages are concerned and everything else, it does affect, the economy But despite this, I think your queries were rightly answered by Mr Jha, that despite all these pressures and constraints on the economy, may not be of a very high percentage, but there is a positive growth which was negative in the past And everybody admits, it it is an acknowledged. In fact that this is the worst drought of the century and in retrospect if you compare the drought situation of 1979-80 which was only a small scale as compared to the present drought, and if you see the rate of inflation at that time, it was more than 20 per cent So, we are trying it. on both sides On the one hand we are trying to mop up our resources, for resource augmentation we are taking pragmatic measures so that burden on the poor people would not be there and at the same time we would have money in our kitty to meet the requirements. On the other hand, we are careful on the demand and supply side also Not only on the supply side but on the demand side also we are taking pragmatic measures. We are having a two-pronged approach, and that is the reason why despite severe strain on the nation's economy, we are able to control the situation.

Many hon Members raised many points, about areas of production, about public sector losses It is true that some of the public sector units are incurring losses, and some public sector units are born with losses; loses are there right from the inception But we have to mend it and, therefore, in my view, the parameter is not the loss or the profit, but as you rightly stated, the per unit cost of production, and the units of production That is a very important aspect. As the hon. Prime Minister also stated the other day, we want our public sector at the commanding height of the economy. .

SHRI NIRMAL CHATTERJEE He understands nothing.

SHRI B. K GADHVI He is my Prime Minister and he understands more than what you all understand, because he understands people's aspiration. Because of historical reasons, such public sector undertakings are there and if there are difficulties, they need to be resolved, and they need to be mended and the Government is keen to do it .

Some hon. Members raised a point about subsidies and asked as to why the subsidies are there; they asked about defence expenditure etc Now, defence expenditure is there not because of our own choice; it is because there are so many other reasons. You cannot have an ostrich view; you cannot have complacency in the matter of defence We cannot compromise with it and we have to see the security environment Everyday we are shouting in this House that the countries which are arming our neighbours to the teeth should stop doing so And if they do not, then whatever may be the cost, the country's security and country's frontiers cannot be put to peril. That is why there may not be any option for us but to have adequate preparedness to meet any contingency at any given time The hon Member talked about subsidy, about cash compensation of about Rs 100 crore Some say subsidies of Rs 40 lakhs on this or that You all say that this country belongs to farmers and when the question of farmers comes, you say, yes, the country belongs to farmers and agricultural sector must be taken care of, and all incentives on inputs must be given to the farmers We are today giving subsidy to farmers on fertilizers We are selling a 50 Kg urea bag at the rate of Rs 170 odd and if retention cost and other cost is calculated, it comes to Rs. 185 But on each bag we are giving a direct subsidy of Rs 68 And that is why there is growth in agricultural production. Despite this, there is pressure on food stocks

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: There is another way of putting it. You are paying Rs. 105 to the manufacturers of fertilisers, i.e. the Birlas You can put it that way also.

SHRI B K GADHVI. Fertiliser is in various sectors Mr Nirmal Chatterjee, you should know the gamut of the fertiliser industry It is not only in the private sector It is in the Government sector. It is in the co-operative sector as well as in the private sector

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: That is the advantage of the private sector

SHRI B. K. GADHVI: Of course, we have to take care. Now, Sir, this is the reason why despite the drought we have been able to procure more rice in Punjab. That is why we are not undergoing the same suffering which was experienced by the people around the Sahara two years back Despite the vastness of the country and the huge population, despite the severe drought, we have been able to meet the foodgrain requirements of the people and there have been no starvation deaths

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: It is far from true.

SHRI B K GADHVI: It is true.

एक माननीय सदस्य : उडीसा में लोग मर रहे है ।

SHRI B. K. GADHVI: It is not a fact It has not been reported to us so far. You can imagine what a commendable performance it is when you take into account the vast population

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) मरे तो हर स्टेट मे हैं पर बीमारी से मरे है खाने की कमी से नहीं ।

SHRI B K. GADHVI: I sincerely congratulate the farmers of this country. You can imagine what would have been the plight and difficulties of the people of this country if the Green Revoluation had not taken place and if the farmers had not put in this tremendous effort (*Interruptions*). The farmers, with a view to giving more encouragement, will continue to receive higher remunerative prices and they will also continue to receive subsidy on fertilisers whether one likes it or not. We want to encourage the farmers in this country.

Some Members raised the point about oilseeds. A greater impetus is being given, incentives are being given, for the production of oilseeds for increasing the production of oilseeds and pulses. He touched about the price rise He is right. There is a little price rise But as I set it, it is contained. Look at the basket of commodities. If you analyse the basket of commodities, out of it about 52 per cent of the commodities are such where you can have no fiscal control, fiscal discipline and fiscal measures They cannot work. Production is the only answer Take, for example, vegetables or fruits or milk I come from Gujarat. I know the difficulties faced by the dairy people Because of the drought the milk yield has gone down; it is very low. Therefore, these are areas where no fiscal measures can work We are trying to meet the difficulties of the people to the maximum possible extent

Mr Jaswant Singh is not here I would like to tell him that Rajasthan is getting the maximum because it is the worst drought-hit State in the country Another valid point which has been raised by hon. Members is about the utilisation of the money. They say that the money which is spent should be well-spent I believe it is not the responsibility of the Members of Parliament and the Government but it is equally the responsibility of the State to see that the money earmarked for a particular purpose is spent for that purpose only We do not make any discrimination.

Some Members referred to the question of diversion of funds, the report of the CAG etc. We have now made it a practice that unless we receive the expenditure statement we are not going to release further money. Naturally, money meant for a marriage ceremony cannot be spent on a funeral. That is why these measures are taken

Sir, as far this measure of raising revenue through surcharge is concerned, I

[Shri B K. Gadhvi]

am thankful to the hon Members There has hardly been any criticism of this measure. Everybody has welcomed it Some people have objected to the point of principle of propriety and other things It shows our own collective participation in our efforts to meet the difficulties of the people in the best possible manner

श्री शरद यादव . उपसभाध्यक्ष महोदय, इनकी केबिनेट के एक मदस्य की लडकी की शादी मे फिजूलखर्ची हुई है । इस संबंध मे 5–7 मदस्यों ने कहा है । मंत्री महोदय को इस बारे मे भी कुछ बोलना चाहिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You need not answer all the points There is no point of order

SHRI B K. GADHVI: Some of the Members have raised the points, like some projects in Nepal which we can do with the help of Nepal and other things. Some Members have raised the points concerning various Ministries I assure the hon. Members that I will collect those points and send them to various Ministries. They will look into those points.

One point Mr. Narayanasamy wanted to be clarified and that was about the fabric duty. He can meet me in my office but I may inform him that that matter has been sorted out The original notification has been substituted with the new one. Now there is no difficulty with the powerloom sector and the duty structure has been rationalised.

With those words I recommend this Bill for consideration of the House.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA Mr. Poojari had given an assurance that tax evasion will not be tolerated I have referred to 8 or 10 houses Thapar. Reliance *(Interruptions)* We are going to pay the tax and and we are going to return the Bil We will have to pay more tax, but I want to know whether you are going to book the tax-evaders.

SHRI B. K. GADHVI: I am answering your point. You were not present when I answered yesterday. at 1 00 O'clock in the night. I have already started that we are not going to let off any economic offenders.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: What about these companies?

SHRI B. K. GADHVI There are some of the recoverable amounts from various companies and big houses. Those amounts are blocked because of the court stay orders. We are trying to expedite those cases.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Mr. Thaper has accepted ...

SHRI B. K. GADHVI: I would not go into individual cases.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I will now put Mr. Jaswant Singh's Statutory Resolution to vote. The question is:

"That this House disapproves of the Finance (Amendment) Ordinance, 1987 (No. 6 of 1987), promulgated by the President on the 19th September, 1987."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I will now put Shri B K Gadhvi's Bill to vote. The question is:

"That the Bill to amend the Finance Act, 1987, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI B. K. GADHVI: I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

श्री राम अवधेश सिंह : मंत्री जी ने हमारे सवालों का जवाब दे दिया है क्या ? मैं समझता हूं कि इन्होंने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया है ।

श्री कल्पनाथ राय : आप यहां थे ही नहीं तो आपकी बातों का जवाब क्या देते ।

The Vice-Cchairman (**Dr. Bapu Kaldate**) in the Chair

THE REGIONAL RURAL BANKS (AMENDMENT) BILL, 1987.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Regional Rural Banks Act, 1976, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, Regional Rural Banks were first constituted by Government in October, 1975 under RRB Ordinance, 1975, which was later substituted by the Regional Rural Banks Act, 1976. They were conceived mainly as low cost institutions staffed by persons residing within the jurisdiction of the area of operation, namely, one or two districts for each RRB to ensure that in their functioning the RRB observed the utmost economy. At present, there are 196 Regional Rural Banks covering 357 districts in 23 States in the country

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal). Excuse me, what is the present figure of number of districts covered?

SHRI JANARDHAN POOJARI: 357 districts in 23 States. These banks have a network of about 13,000 branches The RRBs have mobilised deposits amounting to Rs. 1763 crores and given loans aggregating Rs 1846 crores. The total staff of RRBs comprise of 24067 officers, 22178 clerks and 631 subordinate staff as on 31-12-1986

The RRB Act contains various provisions regarding incorporation, regulation and working of RRBs. The present Bill seeks to make amendments to the main Act in the light of the experience gained in the administration of this Act during the last over 10 years. While commending the Bill for the consideration of the House, I shall confine myself to explain some of the more important provisions contained in the Bill.

At present, in terms of Section 6(1) of RRB Act, the issued capital of each RRB shall be Rs. 25 lakhs. In view of the growth in business, it is desirable that issued capital of Rs. 25 lakhs which was fixed more than 10 years ago should be revised upwards, and fixed between Rs. 25 lakhs and Rs. one crore for each RRB. This will enable the RRB to meet additional expenditure on account of the opening of branches in remote rural areas, servicing large numbers of borrowal accounts and training of staff etc. Simultaneously, the authorised capital is also being increased from Rs. 1 crore at present to Rs. 5 crores.

The Board of Directors of a RRB consists of a Chairman and not more than 8 directors to be nominated by the Central Government, the State Government and the sponsor bank. It has been the practice to nominate two non-officials on the Board of each RRB, one from quota of the Central Government and the other from sponsor bank. The other directors are officials of the sponsor bank, the State Government and the Reserve Bank of India In the interest of administrative simplicity, it is proposed that two non-officials may be nominated by the Central Government